



**SSC
WALLAH**

दक्ष करेंट अफेयर्स जून - 2026

रोहित जैन RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त

DRDO और भारतीय नौसेना ने NASM-SR
का पहला सल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया



सुर्वेदु अधिकारी: पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री

विजय 'थलापति': तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री;
सामाजिक न्याय के नए युग का वादा

SSC CGL, CHSL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

लेखक के विचार

- लेखकों के विचार और मत उनके अपने हैं, और जरूरी नहीं कि यह करंट अफेयर्स पत्रिका या फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबिंबित करें। उन्हें लेखक या लेखकों के व्यक्ति के दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। पत्रिका के विज्ञापन में बताए गए विचारों और विचारों का फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड समर्थन नहीं करता है, न ही यह उनमें किए गए किसी भी दावे की सत्यता को प्रमाणित करता है। यद्यपि पत्रिका में प्रकाशित जानकारी की शुद्धता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती गई है, न तो प्रकाशक, संपादक और न ही इसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी गलत, संक्षिप्त, निरस्त, छोड़े गए या गलत तरीके से डाले गए डेटा के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- सभी अधिकार फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सुरक्षित हैं। प्रकाशक के लिखित सहमति के बिना, इस प्रकाशन के किसी भी भाग का पुनरुत्पादन नहीं बनाया जा सकता है, पुनः इसे किसी भी रूप में रखा नहीं जा सकता है, या किसी भी तरह से प्रसारित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्य किसी भी रूप में हो।

समावेश

1. राष्ट्रीय समाचार	1
2. अंतरराष्ट्रीय समाचार	9
3. राज्य समाचार.....	13
4. व्यवसाय और अर्थव्यवस्था	20
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	26
6. रक्षा समाचार.....	29
7. नियुक्तियाँ.....	33
8. समझौता ज्ञापन.....	38
9. शिखर सम्मेलन	41
10. रिपोर्ट्स और सूचकांक.....	43
11. खेल समाचार	47
12. पुरस्कार और सम्मान समाचार.....	51
13. सरकारी योजनाएँ.....	54
14. निधन समाचार.....	56
15. पुस्तकें और लेखक समाचार.....	58
16. महत्वपूर्ण दिवस समाचार	59

शेखा झील पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल, संख्या 99 पहुँची



- शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे यह भारत का अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला 99वां आर्द्रभूमि स्थल बन गया है।
- यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के निकट स्थित है और राज्य का 12वां रामसर स्थल है।
- रामसर सम्मेलन के तहत मिली यह मान्यता इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता संरक्षण के लिए।
- शेखा झील जैसी आर्द्रभूमियाँ कार्बन अवशोषण, बाढ़ नियंत्रण और जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- इस नए शामिल होने के साथ भारत 100 रामसर स्थलों के लक्ष्य के और करीब पहुँच गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

जैव विविधता शासन मजबूत करने हेतु 5 वर्षीय परियोजना शुरू



- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय परियोजना (2025–2030) शुरू की है।
- इस परियोजना को 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त है तथा इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों और संस्थाओं को सशक्त बनाना है।
- यह परियोजना ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में जैव विविधता संरक्षण को शामिल करने और नवाचारी वित्तपोषण तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- यह पहल भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है।
- तमिलनाडु में यह परियोजना सत्यमंगलम परिदृश्य क्षेत्र को कवर करेगी, जिसमें मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
- मेघालय में यह परियोजना गारो हिल्स क्षेत्र पर केंद्रित होगी, जिसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सिजू वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- यह परियोजना पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संरक्षण परिणामों और जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है।
- यह भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना, वैश्विक 30×30 जैव विविधता लक्ष्य और पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

स्थैतिक बिंदु

- एनबीए – स्थापना वर्ष 2003
- जीईएफ – वैश्विक पर्यावरण वित्तपोषण संस्था

भारत ने 2031–35 अवधि के लिए संशोधित जलवायु लक्ष्य पेश किया



- भारत ने अपने तीसरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) को संशोधित जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- देश ने वर्ष 2005 के आधार स्तर की तुलना में 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में कम-से-कम 47% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत ने 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 60% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा है, जिसे वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त से समर्थन मिलेगा।
- इसके साथ ही, देश ने वन और वृक्ष आवरण बढ़ाकर 3.5–4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
- संशोधित लक्ष्यों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त है और ये पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।
- एनडीसी स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी जलवायु कार्य योजनाएँ होती हैं, जिन्हें देशों को समय-समय पर अद्यतन करना होता है।
- यह भारत की तीसरी एनडीसी प्रस्तुति है। इससे पहले वर्ष 2015 और 2022 में एनडीसी प्रस्तुत की गई थीं, जो जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।

स्थैतिक बिंदु

- एनडीसी – पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्य
- यूएनएफसीसीसी – वैश्विक जलवायु रूपरेखा संस्था

लद्दाख के उपराज्यपाल सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी



- पाँच नए जिलों के गठन के बाद लद्दाख में अब कुल 7 जिले हो गए हैं। इससे पहले यहाँ केवल 2 जिले — लेह और कारगिल — थे।
- इसकी घोषणा विनय कुमार सक्सेना द्वारा की गई।
- नवगठित जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही स्थानीय मांगें पूरी हुई हैं।

- इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करना है।
- इसके माध्यम से तेज सेवा वितरण, बेहतर प्रशासन और बुनियादी ढाँचे की पहुँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
- इस प्रस्ताव को अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- यह कदम क्षेत्रीय विकास के लिए नरेंद्र मोदी के विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है तथा इससे रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्थैतिक बिंदु

- लद्दाख – वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना
- राजधानी – लेह

1 मई 2026 से भारत में नए ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू



- भारत 1 मई 2026 से सुरक्षित, पारदर्शी और अधिक जवाबदेह गेमिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम (प्रोगा) 2025 के तहत नए ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू करेगा।
- सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण भारत (ओजीएआई) की स्थापना करेगी, जो नियमों के अनुपालन की निगरानी, शिकायतों के निस्तारण और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के विनियमन का कार्य करेगा।
- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ अत्यधिक खर्च, मानसिक नुकसान, गोपनीयता संबंधी खतरे तथा हानिकारक या अनुचित सामग्री से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय लागू करेंगी।
- नए नियम गेमप्ले, वित्तीय लेन-देन और उपयोगकर्ताओं की सूचित पसंद में पारदर्शिता बढ़ाकर जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करेंगे।
- अधिकांश ऑनलाइन खेलों के लिए अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि हानिकारक या जोखिमपूर्ण गतिविधियों वाले खेलों पर कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं।
- ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म और कुछ गेमिंग कंपनियों को उपयोगकर्ता संख्या, वित्तीय लेन-देन और कंपनी की उत्पत्ति जैसे मानकों के आधार पर ओजीएआई में पंजीकरण कराना होगा।

सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय ने एशिया की पहली यूनेस्को जेंडर समावेशन चेयर शुरू की



- सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यूनेस्को के सहयोग से जेंडर समावेशन और कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की।
- इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाकर सशक्त बनाना है।
- इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने “वर्क के भविष्य में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका” विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया।
- यूनेस्को चेयर का मुख्य उद्देश्य भविष्य के रोजगार क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को कम करना है, जहाँ पारंपरिक रूप से महिलाओं की भागीदारी कम रही है।
- यह पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- इस कार्यक्रम का नेतृत्व सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो-चांसलर डॉ. स्वाति मुजुमदार द्वारा किया गया।
- इस पहल के तहत 10,000 से अधिक वंचित बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें उन्नत प्रौद्योगिकियों का अनुभव प्राप्त हुआ।
- कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कई उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज के साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए।
- इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को-यूनेवोक, आईबीएम, कैपजेमिनी, बार्कलेज और लार्सन एंड टुब्रो जैसी संस्थाओं ने भाग लिया।

जनगणना 2027 में भारत की पहली डिजिटल गणना प्रक्रिया शुरू होगी

- जनगणना 2027 को भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें मोबाइल आधारित डेटा संग्रह और स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होगी।
- 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जनगणना 2027 में जातीय गणना को मंजूरी दी।



- जनगणना 2027 को भारत की 16वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना बताया गया है।
- इस जनगणना प्रक्रिया के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी।
- जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को रात्रि 12:00 बजे निर्धारित की गई है।
- जनगणना 2027 के प्रथम चरण में अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना आयोजित की जाएगी।
- द्वितीय चरण के अंतर्गत फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी, जिसमें विस्तृत जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आँकड़े एकत्र किए जाएंगे।
- गणना प्रक्रिया की लगभग वास्तविक समय में निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

पहली बार यात्री ट्रेन के माध्यम से जम्मू सीधे कश्मीर से जुड़ा



- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तारित श्रीनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी स्टेशन तक हरी झंडी दिखाई।
- इससे जम्मू-कश्मीर को पहली बार निर्बाध रेल कॉरिडोर के माध्यम से सीधी यात्री ट्रेन कनेक्टिविटी प्राप्त हुई।
- उच्च यात्री मांग को देखते हुए जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच किया गया।
- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना ने कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान किया।
- यूएसबीआरएल परियोजना के तहत चिनाब रेल पुल को विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल बताया गया।

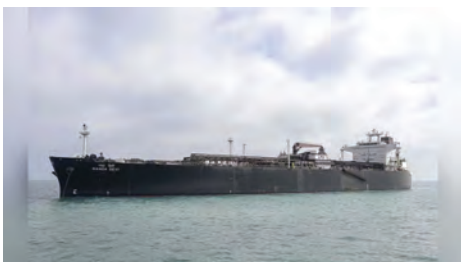
- रेल क्षमता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तवी स्टेशन के पुनर्विकास तथा काजीगुंड-बारामूला रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया गया।

एनएचआई ने गुजरात में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की



- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने गुजरात के सूत-भरूच मार्ग पर एनएच-48 स्थित चोरयासी टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली शुरू की।
- एमएलएफएफ प्रणाली बैरियर-रहित टोल संग्रह की सुविधा देती है, जिससे वाहन बिना रुके गुजर सकते हैं और यातायात प्रवाह बेहतर होता है।
- यह प्रणाली ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और फास्टैग तकनीक का उपयोग कर निर्बाध और संपर्करहित टोल संग्रह सुनिश्चित करती है।
- पहले ही दिन लगभग 41,500 वाहनों ने टोल प्वाइंट पार किया, जिससे इसकी सफल कार्यप्रणाली प्रदर्शित हुई।
- इससे जाम, यात्रा समय, ईंधन खपत और वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे परिवहन दक्षता बढ़ेगी।
- उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना होगा, अन्यथा भुगतान न होने पर ई-नोटिस जारी किया जाएगा।
- यदि 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो दोगुना टोल शुल्क लागू होगा और लगातार डिफॉल्ट की स्थिति में वाहन का फास्टैग वाहन पोर्टल (वाहन) के माध्यम से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
- एमएलएफएफ प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने, परिचालन लागत घटाने और टोलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।

केंद्र ने वाडिनार में 1,570 करोड़ रुपये की जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गुजरात के वाडिनार में 1,570 करोड़ रुपये की जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी।
- इस परियोजना को दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
- यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना होगी, जिसमें 650 मीटर लंबा जेड्डी, फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएँ और समुद्री अवसंरचना विकसित की जाएगी।
- इस सुविधा का उद्देश्य भारत में 230 मीटर से अधिक लंबाई वाले बड़े जहाजों की मरम्मत क्षमता की कमी को दूर करना है।
- वाडिनार का गहरा ड्राफ्ट, रणनीतिक स्थान और मुंद्रा एवं कांडला जैसे बंदरगाहों के निकट होना इसे जहाज मरम्मत संचालन के लिए उपयुक्त बनाता है।
- यह परियोजना विदेशी शिपयार्ड पर निर्भरता कम करेगी, विदेशी मुद्रा की बचत करेगी और बंदरगाह प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाएगी।
- इससे समुद्री सहायक सेवाओं, एमएसएमई और क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- यह पहल मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है।

सीजेआई ने 'वन केस वन डेटा' पहल और एआई चैटबॉट 'सु सहाय' लॉन्च किया



- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की घोषणा की।
- न्यायपालिका ने "वन केस वन डेटा" पहल शुरू की, जिसके तहत उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों की जानकारी को एकीकृत प्रणाली में जोड़ा जाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में केस प्रबंधन, डेटा एकीकरण और न्यायिक कार्यक्षमता में सुधार करना है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के साथ एकीकृत एआई आधारित चैटबॉट "सु सहाय" भी लॉन्च किया।
- यह चैटबॉट नागरिकों को अदालत से संबंधित सेवाओं, दिशा-निर्देशों और जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करेगा।
- नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से इस चैटबॉट का विकास किया है।

- यह पहल डिजिटल प्रशासन और न्याय तक पहुँच को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल परिवर्तन में सहयोग देने के लिए रजिस्ट्री अधिकारियों और बार सदस्यों के योगदान की सराहना की।

स्थैतिक बिंदु

- नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- तालुका न्यायालय भारत में उप-जिला स्तर पर कार्य करते हैं।

भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 44 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी



- भारत ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 44 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे देश की कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 150 गीगावॉट तक पहुँच गई।
- मार्च 2026 तक भारत की कुल सौर क्षमता 150.2 गीगावॉट एसी हो गई, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया।
- तेजी से हुए इस विस्तार का प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं की स्थापना रही, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर वार्षिक क्षमता वृद्धि करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया।
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के माध्यम से सौर क्षेत्र को नीतिगत समर्थन प्रदान किया।
- पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं ने रूफटॉप सोलर, सौर पंप और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया।
- भारत ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 14.4 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी, जो वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जोड़ी गई 7.7 गीगावॉट क्षमता से लगभग दोगुनी थी।
- वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 276.5 गीगावॉट तक पहुँच गई, जिसमें कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 51.7% रही।
- सौर ऊर्जा विस्तार के मामले में भारत वार्षिक क्षमता वृद्धि में अमेरिका से आगे रहा, जबकि वैश्विक तुलना में चीन और यूरोपीय संघ के बाद स्थान पर रहा।

मक्का भारत में इथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बना



- 12 मई 2026 तक मक्का भारत में इथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया, जिसने अनाज आधारित इथेनॉल योगदान में गन्ने को पीछे छोड़ दिया।
- इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 की पहली छमाही में मक्का आधारित इथेनॉल उत्पादन 182 करोड़ लीटर तक पहुँच गया।
- भारत की कुल इथेनॉल आपूर्ति 515 करोड़ लीटर से अधिक हो गई, जो 1,059 करोड़ लीटर के अनुबंधित लक्ष्य का लगभग 49% है।
- अनाज आधारित डिस्टिलरी ने लगभग 333 करोड़ लीटर इथेनॉल का योगदान दिया, जिसमें मक्का प्रमुख स्रोत रहा।
- कम पानी की आवश्यकता और कई मौसमों में खेती के अनुकूल कम अवधि वाले चक्र के कारण मक्का को गन्ने की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई।
- उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026-27 में इथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिए मक्का की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 11.3 लाख हेक्टेयर करने की योजना बनाई।
- भारत में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है और मक्का पोएसी कुल का पौधा है, जिसका उपयोग औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन में व्यापक रूप से किया जाता है।
- वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड के तहत इथेनॉल आवश्यकता 15 बिलियन गैलन पर बरकरार रखी।

ईसीआई ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत की



- भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई 2026 को 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत की।

- इस अभियान के तहत लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया गया।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए घर-घर गणना और मतदाता विवरण सुधार की क्षेत्रीय प्रक्रिया है।
- इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल थे।
- इसके अलावा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी शामिल किया गया।
- मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अद्यतन मतदाता सूची बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया।
- अंतिम अद्यतन मतदाता सूची 6 सितंबर 2026 को प्रकाशित किए जाने की निर्धारित थी।

न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया गया



- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देशभर में न्यायालय अवसंरचना के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने हेतु न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया।
- इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सौंपी गई। इसमें कलकत्ता, पंजाब एवं हरियाणा तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी शामिल किया गया।
- समिति को न्यायालयों, वादकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में कमी का आकलन कर सुधार संबंधी सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया।
- इसे न्यायालयों के कंप्यूटीकरण और नागरिक केंद्रित ई-कोर्ट सेवाओं को मजबूत करने की समीक्षा का कार्य भी दिया गया।
- समिति ने देश में न्यायिक अवसंरचना उन्नयन के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये के अनुमानित आवंटन का प्रस्ताव दिया।
- अंतरिम रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपे जाने की निर्धारित थी, ताकि आगे सरकारों द्वारा उस पर विचार किया जा सके।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया



- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 15 मई 2026 को धार जिले स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया।
- अदालत ने माना कि विवादित संरचना देवी सरस्वती (वाग्देवी) को समर्पित हिंदू मंदिर थी।
- निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें दोनों समुदायों के लिए सीमित पूजा व्यवस्था की अनुमति दी गई थी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मार्च से जून 2024 के बीच इस स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, जिसमें मंदिर मूल की संरचनाओं के संकेत मिले थे।
- इस मामले में पूजा अधिकारों को लेकर विभिन्न दावे शामिल थे, जिनमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिकाएँ भी शामिल थीं।
- अदालत ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक अभिलेखों का हवाला दिया, जिनमें भोजशाला को संस्कृत शिक्षा के केंद्र और सरस्वती मंदिर स्थल के रूप में वर्णित किया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- यह स्थल परंपरागत रूप से राजा भोज (परमार वंश, 11वीं शताब्दी) से जुड़ा माना जाता है।
- हिंदू परंपरा इसे देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर और शिक्षा केंद्र के रूप में पहचानती है।
- यह संस्कृत विद्वता और प्राचीन शिक्षा परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है।
- इस संरचना में मध्यकालीन मंदिर शैली निर्माण के स्थापत्य और शिलालेख संबंधी प्रमाण पाए जाते हैं।

संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी



- संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 34 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया।
- इस कदम का उद्देश्य बढ़ते लंबित मामलों को कम करना और देशभर में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
- संशोधन के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट की कुल कार्यरत संख्या 38 हो जाएगी।
- न्यायिक दक्षता और न्याय तक पहुँच से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका एवं विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने यह प्रस्ताव पेश किया था।
- हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है, जो 80,000 से अधिक हो चुकी है, जिससे न्यायिक प्रशासन पर दबाव बढ़ा है।

स्थैतिक जीके

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना – 28 जनवरी 1950
- सर्वोच्च न्यायालय का स्थान – नई दिल्ली
- संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित है।
- भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश – न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया

नीदरलैंड्स ने 11वीं शताब्दी की चोल ताम्रपट्टिकाएँ भारत को लौटाईं



- नीदरलैंड्स ने लगभग 14 वर्षों के राजनयिक प्रयासों के बाद 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपट्टिकाएँ औपचारिक रूप से भारत को लौटा दीं।

- इन कलाकृतियों की वापसी नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान हुई।
- लौटाई गई कलाकृतियाँ आनैमंगलम कॉपर प्लेट्स या लीडेन प्लेट्स के नाम से जानी जाती थीं।
- चोल ताम्रपट्टिकाएँ लगभग तीन शताब्दियों तक नीदरलैंड्स में रहीं, जिसके बाद उन्हें भारत को वापस किया गया।
- इन कलाकृतियों में चोल काल की 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्रपट्टिकाएँ शामिल थीं।
- इन ताम्रपट्टिकाओं पर अंकित शिलालेख राजराजा चोल प्रथम और राजेन्द्र चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित थे।
- ताम्रपट्टिकाओं पर तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में शासन व्यवस्था, भूमि राजस्व, धार्मिक अनुदान और शाही आदेशों से जुड़े अभिलेख अंकित थे।
- ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इन कलाकृतियों को लगभग वर्ष 1712 में नागपट्टिनम में डच औपनिवेशिक उपस्थिति के दौरान नीदरलैंड्स ले जाया गया था।
- बताया जाता है कि इन ताम्रपट्टिकाओं को फ्लोरेटियस कैम्पर द्वारा ले जाया गया था, जो उस क्षेत्र में ईसाई मिशनरी गतिविधियों से जुड़े थे।
- बाद में वर्ष 1862 में इन कलाकृतियों को लीडेन विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया और इन्हें विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संरक्षित रखा गया।
- भारत ने वर्ष 2023 में सांस्कृतिक संपत्ति को उसके मूल देशों में लौटाने को बढ़ावा देने वाली अंतर-सरकारी समिति (आईसीपीआरसीपी) के माध्यम से यूनेस्को के समक्ष औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठाया था।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय कैप्टागॉन नेटवर्क के खिलाफ 'ऑपरेशन रेजपिल' शुरू किया



- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 16 मई 2026 को एक अंतरराष्ट्रीय कैप्टागॉन तस्करी गिरोह के खिलाफ 'ऑपरेशन रेजपिल' शुरू किया।
- इस अभियान के तहत लगभग 227.7 किलोग्राम कैप्टागॉन टैबलेट और पाउडर जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 182 करोड़ रुपये आंकी गई। यह भारत में कैप्टागॉन की पहली बड़ी जब्ती मानी गई।
- कैप्टागॉन को फेनेटिलीन और एम्फेटामिन से जुड़ी एक सिंथेटिक साइकोस्टिमुलेंट ड्रग के रूप में पहचाना गया, जिसका पश्चिम एशिया और मध्य-पूर्व में व्यापक दुरुपयोग होता है।

- लगभग 31.5 किलोग्राम कैप्टागॉन टैबलेट नई दिल्ली के नेब सराय क्षेत्र से बरामद की गई, जिन्हें सऊदी अरब के जेद्दा भेजी जाने वाली चपाती काटने की मशीन में छिपाया गया था।
- इसके अलावा 196.2 किलोग्राम कैप्टागॉन पाउडर मुंद्रा बंदरगाह पर एक शिपिंग कंटेनर से बरामद किया गया, जो सीरिया से ऊन की खेप के रूप में छिपाकर लाया गया था।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की केंद्रीय मादक पदार्थ विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
- भारत में मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 के तहत नियंत्रित किया जाता है।

अंतरिक्ष विभाग ने गुजरात और तमिलनाडु में अंतरिक्ष सुविधाओं को मंजूरी दी



- अंतरिक्ष विभाग ने 22 मई 2026 को भारत के निजी अंतरिक्ष विनिर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज को मंजूरी दी।
- इन सुविधाओं का विकास भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के सहयोग से किया गया।
- कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज को रॉकेट और उपग्रह हार्डवेयर के परीक्षण, सत्यापन और एकीकरण के लिए साझा केंद्रों के रूप में विकसित किया गया।
- गुजरात के अहमदाबाद के पास खोराज में अंतरिक्ष यान और पेलोड प्रणाली निर्माण के लिए स्पेस मैनुफैक्चरिंग पार्क को मंजूरी दी गई।
- तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कुलसेकरपट्टनम स्थित आगामी प्रक्षेपण परिसर के निकट स्पेस व्हीकल्स क्लस्टर को मंजूरी दी गई।

- तमिलनाडु की यह सुविधा पूर्ण प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों के निर्माण, परीक्षण और एकीकरण के लिए विकसित की जाएगी।
- केंद्र सरकार ने तूतीकोरिन की इस विशेष सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
- दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को भूमि, भवन और नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- इन-स्पेस को तकनीकी प्रणालियों की खरीद, स्थापना और प्रारंभिक संचालन की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद स्वामित्व राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा।

भारत ने अधिक एथेनॉल मिश्रण के लिए E30 पेट्रोल मानकों को अधिसूचित किया



- भारत ने 18 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से E30 तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नए पेट्रोल मानकों को अधिसूचित किया।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल मिश्रणों के लिए विनिर्देश जारी किए।
- E20 और E30 का अर्थ क्रमशः 20% और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से है।
- ये नए मानक 15 मई 2026 से प्रभावी हुए और भविष्य में अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए तकनीकी ढाँचा प्रदान किया।
- इन मानकों में निर्जल एथेनॉल को शामिल किया गया, जो बहुत कम जल मात्रा वाला एथेनॉल होता है और ईंधन मिश्रण में उपयोग किया जाता है।
- सरकार ने E85 ईंधन, जिसमें 85% एथेनॉल होता है, की व्यवहार्यता और उच्च एथेनॉल अवसंरचना की तैयारी की भी समीक्षा की।
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को E10 और E20 अनुरूप वाहनों पर E25 ईंधन के प्रभाव का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

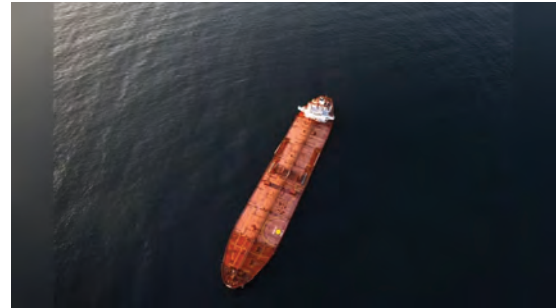


यूएई ने ओपेक और ओपेक+ से बाहर होने की घोषणा की



- संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक+ से बाहर हो जाएगा, जिससे लगभग छह दशक पुरानी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यूएई ने तेल उत्पादन कोटा संबंधी प्रतिबंधों से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और तेल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
- देश ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है और वह वैश्विक ऊर्जा मांग को पूरा करना चाहता है।
- ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन का समन्वय करने और वैश्विक तेल कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई थी।
- यूएई वर्ष 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था और संगठन के प्रमुख तेल उत्पादक सदस्यों में से एक बन गया था।
- विश्लेषकों का मानना है कि यूएई के बाहर होने से वैश्विक तेल उत्पादन और बाजार स्थिरता पर ओपेक का प्रभाव कमजोर हो सकता है।
- इस कदम से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और अधिक आपूर्ति के कारण वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव बन सकता है।
- यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक तेल परिवहन के महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं।
- यूएई की कम तेल उत्पादन लागत देश को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के दौरान भी लाभ में बने रहने में सहायता करती है।
- इस निर्णय से ओपेक में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सऊदी अरब पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है।

अमेरिका ने होर्मुज मार्ग से जहाजों की सुरक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू किया



- डोनाल्ड ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य से फँसे विदेशी जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी।
- इस पहल का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण फँसे जहाजों की सहायता करना है, जिनमें से कई खाद्य सामग्री, पानी और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे हैं।
- अमेरिका ने चेतावनी दी कि इस अभियान में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने पर ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- यह कदम अमेरिका और इजराइल से जुड़े ईरान संघर्ष के बाद क्षेत्र में समुद्री आवाजाही बाधित होने की स्थिति के बीच उठाया गया है।
- तनाव के बावजूद अमेरिका ने संकेत दिया कि ईरान के साथ सकारात्मक समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता जारी है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एमईआईडीपी : ओमान तक भारत का 40,000 करोड़ रुपये का समुद्री ऊर्जा कॉरिडोर

- भारत दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए ओमान से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपये

की गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है।



- प्रस्तावित समुद्री पाइपलाइन अरब सागर से होकर गुजरेगी और रणनीतिक रूप से संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र को बायपास करने की संभावना है।
- सरकारी मंजूरी और व्यवहार्यता स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 5 से 7 वर्ष लग सकते हैं।
- गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियाँ विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं।
- यह पाइपलाइन लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी होगी और करीब 3,450 मीटर की गहराई पर बिछाई जाने वाली विश्व की सबसे गहरी समुद्री पाइपलाइनों में शामिल हो सकती है।
- परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 31 एमएमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) प्राकृतिक गैस परिवहन का लक्ष्य रखा गया है।
- यह प्रस्ताव मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन (एमआईडीपी) अवधारणा से जुड़ा है, जिस पर पहली बार 1990 के दशक के अंत में चर्चा हुई थी।
- भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% आवश्यकता आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है।

अन्य जानकारी

- केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री – हरदीप सिंह पुरी
- ओमान की राजधानी – मस्कट

कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

- नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया और एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया।



- 56 वर्षीय पर्वतारोही ने वर्ष 2026 के वसंत पर्वतारोहण सत्र के दौरान नेपाल समयानुसार सुबह लगभग 10:12 बजे 8,848.86 मीटर ऊँची चोटी पर पहुँचने में सफलता हासिल की।
- कामी रीता 14 पीक्स एक्सपीडिशन द्वारा आयोजित अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहियों को सफलतापूर्वक शिखर तक पहुँचाया।
- “एवरेस्ट चैन” के नाम से प्रसिद्ध कामी रीता ने पहली बार वर्ष 1994 में एवरेस्ट फतह किया था और इसके बाद से लगभग हर वर्ष इस शिखर पर चढ़ाई की है।
- पर्वतारोही ल्हाक्पा शेरपा ने भी 11वीं बार एवरेस्ट फतह कर महिलाओं में अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ाया।

स्थैतिक जीके

- माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई 8,848.86 मीटर है।
- यह हिमालय पर्वतमाला में नेपाल-चीन सीमा पर स्थित है।
- सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने वर्ष 1953 में पहली बार एवरेस्ट शिखर पर सफलता प्राप्त की थी।

डब्ल्यूएचओ ने कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप को पीएचईआईसी घोषित किया



- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी) घोषित किया।

- यह प्रकोप इबोला वायरस के दुर्लभ बुंड़ीबुंग्यो स्ट्रेन से जुड़ा है, जिसके लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डीआरसी के इतुरी प्रांत में 246 से अधिक संदिग्ध मामले और 80 से अधिक मौतें दर्ज की गईं, जबकि युगांडा ने कंपाला में आयातित मामलों की पुष्टि की।
- डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि सीमापार आवाजाही और सीमित स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण यह प्रकोप क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा खतरा पैदा करता है।
- आपातकालीन घोषणा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता जुटाना, निगरानी व्यवस्था मजबूत करना, सीमा स्वास्थ्य जांच बेहतर करना तथा चिकित्सा विशेषज्ञों और आवश्यक आपूर्ति की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करना है।

स्थैतिक जीके

- इबोला वायरस की पहली पहचान वर्ष 1976 में डीआरसी की इबोला नदी के पास हुई थी।
- डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय – जेनेवा
- पीएचईआईसी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के तहत सबसे उच्च चेतावनी स्तर है।

इंडोनेशिया के डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट, राख का गुबार 5,000 मीटर तक पहुँचा



- इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकु प्रांत के हलमहेरा द्वीप स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे ज्वालामुखीय राख लगभग 5,000 मीटर ऊँचाई तक आसमान में फैल गई और आसपास के निवासियों के लिए नई सुरक्षा चेतावनियाँ जारी की गईं।
- विस्फोट के दौरान घने धूसर राख के बादल और तेज धमाकेदार आवाजें सुनाई दीं, जबकि अधिकारियों ने लोगों को क्रेटर के आसपास निर्धारित खतरे वाले क्षेत्र में गतिविधियाँ न करने की सलाह दी।
- इंडोनेशिया के ज्वालामुखी एवं भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र (पीवीएमबीजी) ने ज्वालामुखी को अलर्ट लेवल-II पर बनाए रखा और ज्वालामुखीय राख फैलने से श्वसन संबंधी जोखिमों की चेतावनी दी।

- माउंट डुकोनो इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और वर्ष 1933 से लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियों के साथ दशकों से बार-बार विस्फोट देखे गए हैं।
- इंडोनेशिया प्रशांत “रिंग ऑफ फायर” क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण तीव्र विवर्तनिक गतिविधियों के चलते वहाँ भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोटों का खतरा अधिक रहता है।

स्थैतिक जीके

- इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- इंडोनेशिया की राजधानी – जकार्ता
- प्रशांत रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित घोंडे की नाल के आकार का भूकंपीय क्षेत्र है, जो बार-बार आने वाले भूकंपों और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है।

मनोज कुमार शर्मा ने नेपाल के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला



- मनोज कुमार शर्मा ने नेपाल के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।
- नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनकी नियुक्ति संसदीय स्वीकृति के बाद की।
- न्यायमूर्ति शर्मा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला का स्थान लिया और वह छह वर्ष के कार्यकाल तक इस पद पर रहेंगे।
- उन्हें अप्रैल 2019 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश इसी महीने नेपाल की संवैधानिक परिषद द्वारा की गई थी। वह नेपाल के इतिहास में वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले न्यायाधीश बने।
- उन्होंने इससे पहले बुटवल और पाटन की अपीलीय अदालतों सहित कई न्यायिक पदों पर कार्य किया है।

सऊदी अरब भारत-नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया सदस्य बना



- सऊदी अरब आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) का नया सदस्य बन गया, जो भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा — का संरक्षण और सुरक्षा करना है।
- इस गठबंधन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण, आवास सुरक्षा, शिकार-रोधी अभियानों, अनुसंधान और सतत पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।
- सऊदी अरब के शामिल होने से विशेष रूप से रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और संकटग्रस्त वन्यजीव प्रबंधन में तकनीकी साझेदारी और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- भारत ने सऊदी अरब की भागीदारी का स्वागत करते हुए इसे सामूहिक वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकीय स्थिरता पहलों के प्रति बढ़ते वैश्विक समर्थन का संकेत बताया।
- इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की थी।

स्थैतिक जीके तथ्य

- इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है।
- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में भारत में बाघ संरक्षण के लिए की गई थी।

- विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं।
- सऊदी अरब की राजधानी – रियाद
- सऊदी अरब की मुद्रा – सऊदी रियाल

भारत और साइप्रस ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया



- भारत और साइप्रस ने 22 मई 2026 को निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स की नई दिल्ली यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया।
- नरेंद्र मोदी और निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर वार्ता हुई।
- भारत और साइप्रस ने वर्ष 1962 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और व्यापार, समुद्री मामलों तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बनाए रखा है।
- दोनों देशों ने वर्ष 2025–2029 के लिए व्यापार, रक्षा, नवाचार, समुद्री सुरक्षा और निवेश सहयोग को शामिल करते हुए पाँच वर्षीय संयुक्त कार्ययोजना का समर्थन किया।
- भारत और साइप्रस ने अवसंरचना और शिपिंग सहयोग के लिए संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- सुरक्षा सहयोग और संयुक्त कार्य समूहों को मजबूत करने के लिए आतंकवाद-रोधी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
- साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया।
- साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य देश है और वहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 36,000 करोड़ रुपये के गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।
- यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है।
- 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह 6-लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8-लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- इस परियोजना का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा) द्वारा किया गया है।
- इसमें शाहजहांपुर के निकट भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है।
- यह एक्सप्रेसवे संपर्क, लॉजिस्टिक दक्षता तथा वस्तुओं और कृषि उत्पादों के तेज परिवहन को बढ़ावा देगा।
- परियोजना के तहत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मार्ग के किनारे एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) विकसित करने की योजना है।
- इससे रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
- भविष्य में इसे हरिद्वार (उत्तराखंड) से जोड़ने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और मजबूत होगा।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश को प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

स्थैतिक बिंदु

- लंबाई – 594 किलोमीटर
- उत्तर प्रदेश की राजधानी – लखनऊ

आंध्र प्रदेश ने 13,000 करोड़ रुपये का मशरूम मिशन शुरू किया



- आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये के निवेश से अपना पहला मशरूम मिशन शुरू किया।
- मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनाने के उद्देश्य से इस पहल की घोषणा की।
- इस मिशन का लक्ष्य प्रतिवर्ष लगभग 67,500 टन मशरूम उत्पादन करना है, जो बिहार के वर्तमान उत्पादन स्तर से अधिक होगा।
- सरकार ने इस मिशन के तहत राज्यभर में लगभग 1.62 लाख मशरूम उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बनाई है।
- यह पहल मुख्य रूप से छोटे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों पर केंद्रित है, ताकि स्थायी आय सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रत्येक मशरूम उत्पादन इकाई को लगभग 5,000 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- मिशन में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
- सरकार ने कुल परियोजना लागत का लगभग 40% कवर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय सहायता से 5,184 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है।
- मशरूम मिशन से बड़े स्तर पर ग्रामीण रोजगार सृजन और आंध्र प्रदेश में मजबूत कृषि आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित होने की उम्मीद है।

शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया



- वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित किया गया।
- कोलकाता में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा।
- बैठक में अमित शाह भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मोहन चरण माझी सह-पर्यवेक्षक रहे।
- भाजपा की इस जीत के साथ पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष पुराने शासन का अंत हो गया।
- यह चुनाव परिणाम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना गया।
- शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके थे, बाद में वे भाजपा में शामिल हुए।

स्थैतिक बिंदु

- पश्चिम बंगाल की राजधानी – कोलकाता

हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली



- हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 मई 2026 को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया।

- उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को असम विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद शपथ ली।
- एनडीए ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 102 सीटें जीतकर 64 सीटों के आवश्यक बहुमत के आंकड़े को पार किया।
- असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 10 मई 2026 को बहुमत समर्थन का दावा पेश करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जब बहुमत दल या गठबंधन का नेता विधानसभा में बहुमत साबित करता है।

विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सामाजिक न्याय के नए दौर का किया ऐलान



- सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- वह तमिलनाडु वेटी कड़गम (टीवीके) के अध्यक्ष हैं।
- विजय वर्ष 1969 के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर-द्रविड़ दल के नेता बने।
- शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ।
- विजय ने बिना किसी नोट्स या टेलीप्रॉम्प्टर के शपथ ली, जिस पर समर्थकों ने जोरदार उत्साह व्यक्त किया।
- स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, जहाँ बड़ी स्क्रीन पर समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।
- सिनेमा से राजनीति तक उनका सफर तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

स्थैतिक बिंदु

- तमिलनाडु की राजधानी – चेन्नई
- टीवीके की स्थापना विजय ने वर्ष 2024 में की थी।

एन. रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

- एन. रंगासामी ने 13 मई 2026 को पाँचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- लोक निवास, पुडुचेरी में उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।



- उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली।
- पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में एआईएनआरसी, भाजपा, एआईएडीएमके और लक्ष्मिया जननायगा काची शामिल थे।
- पुडुचेरी भारत के आठ केंद्रशासित प्रदेशों में से एक है और यहाँ भारत सरकार केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के तहत विधानसभा व्यवस्था है, जहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है।

वी.डी. सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किया गया



- वी.डी. सतीशन को 14 मई 2026 को संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद केरल का मुख्यमंत्री घोषित किया गया।
- यूडीएफ ने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटें जीतकर 71 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार किया।
- सतीशन केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने और इससे पहले वर्ष 2021 से 2026 तक विपक्ष के नेता रह चुके थे।
- उन्होंने वर्ष 2001 से परवूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 2026 में लगातार छठी बार चुनाव जीता।
- संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी और यह केरल के दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों में से एक रहा है।
- केरल विधानसभा एक सदनीय विधानमंडल के रूप में कार्य करती है, जिसमें 140 निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हुआ था और विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 सीटें है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 33,000 करोड़ रुपये की ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी



- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले में तीन ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी।
- परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,400 मेगावाट होगी।
- मेजा परियोजना चरण-II में 800-800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शामिल होंगी।
- परियोजना में कुल निवेश लगभग 33,000 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- परियोजना को पूरा करने की समयसीमा पाँच वर्ष निर्धारित की गई है।
- यह परियोजना निम्न के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है:
 - ◆ एनटीपीसी लिमिटेड
 - ◆ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम (यूपीआरवीयूएन)

अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय ने एतोर गिदी उत्सव मनाया



- अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय ने समृद्धि, सांस्कृतिक पहचान और कृषि परंपराओं के प्रतीक के रूप में एतोर गिदी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया।
- यह उत्सव मुख्य रूप से अपर सियांग और ईस्ट सियांग क्षेत्रों में मनाया जाता है और आदि जनजाति की गहरी आध्यात्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को दर्शाता है।
- समुदाय के लोगों ने अच्छी फसल, शांति और सामुदायिक सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हुए पारंपरिक लोक नृत्य, अनुष्ठान और गीत प्रस्तुत किए।
- बुजुर्गों ने इस अवसर पर युवा पीढ़ी को स्वदेशी ज्ञान, रीति-रिवाज, मौखिक परंपराएँ और सांस्कृतिक मूल्य सौंपे।

- उत्सव में पारंपरिक आदि वेशभूषा, बाँस शिल्प और स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे पूर्वोत्तर की जनजातीय विरासत और पर्यटन को बढ़ावा मिला।
- आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख स्वदेशी जनजातियों में से एक है और यह तिब्बती-बर्मी भाषा समूह से संबंधित है।

अतिरिक्त जानकारी

- अरुणाचल प्रदेश की राजधानी – ईटानगर
- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री – पेमा खांडू
- अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार – सोलुंग, लोसार, मोपिन, न्योकुम और ड्री
- अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है।

राजस्थान ने 'यशोदा माताओं' के माध्यम से स्तन दूध दान को बढ़ावा दिया



- राजस्थान ने नवजात शिशु देखभाल सहायता के लिए नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल के तहत 'यशोदा कार्यक्रम' के माध्यम से स्तन दूध दान को बढ़ावा दिया।
- बाड़मेर जिला अस्पताल स्थित मदर मिलक बैंक ने 4 मार्च 2018 को शुरू होने के बाद से 29,882 यूनिट मानव दूध एकत्र किया।
- मई 2026 तक बाड़मेर मिलक बैंक ने 3,165 नवजात शिशुओं को सहायता प्रदान की और 3,523 यशोदा माताओं का पंजीकरण किया।
- दान किए गए दूध को माइनस 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा गया और उचित जांच व प्रसंस्करण के बाद इसे छह महीने तक संरक्षित किया गया।
- संग्रहित स्तन दूध को संग्रह और वितरण से पहले एचआईवी तथा अन्य संक्रमणों की जांच से गुजारा गया।
- जयपुर का 'जीवन धारा' मिलक बैंक 27 मार्च 2015 को शुरू किया गया राजस्थान का पहला सरकारी मानव दुग्ध बैंक था।
- भीलवाड़ा स्थित 'आंचल मदर मिलक बैंक' में बड़े स्तर पर दूध दान हुआ, जिससे 5,000 से अधिक शिशुओं को पोषण सहायता मिली।

- यशोदा कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए तत्काल और विशिष्ट स्तनपान को बढ़ावा देना था।

पश्चिम बंगाल ने 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' की घोषणा की



- पश्चिम बंगाल ने 11 मई 2026 को नई राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रस्तावित 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' की घोषणा की।
- इस योजना को महिलाओं केन्द्रित कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया, जिसके तहत बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया।
- अन्नपूर्णा भंडार योजना को पश्चिम बंगाल की पूर्व 'लक्ष्मी भंडार योजना' के उन्नत या प्रतिस्थापन रूप में प्रस्तुत किया गया।

कर्नाटक ने उपस्थिति के लिए 'कर्तव्य-केएएमएस' ऐप शुरू किया



- कर्नाटक ने सरकारी स्कूलों और कार्यालयों के कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए 'कर्तव्य-केएएमएस' (कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम) ऐप शुरू किया।

- यह प्रणाली राज्यभर के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए विकसित की गई।
- यह ऐप कार्यस्थल पर उपस्थिति सत्यापन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फेस रिकग्निशन और जियो-फेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है।
- कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से प्रतिदिन दो बार “इन टाइम” और “आउट टाइम” के रूप में उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
- यह प्रणाली 1 मई 2026 से सरकारी विभागों में पहले से लागू बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था का स्थान ले चुकी है।
- केएएमएस को एचआरएमएस और स्टूडेंट्स अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि प्रशासनिक डेटा प्रबंधन को मजबूत किया जा सके।
- कर्नाटक में इस ऐप का विकास और कार्यान्वयन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (ई-गवर्नेंस) द्वारा किया गया।
- इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विभागों के 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को शामिल करने की योजना बनाई गई।

बरपाली ओडिशा की संबलपुरी हथकरघा परंपरा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा



- ओडिशा के बरगढ़ जिले का बरपाली अपने पारंपरिक टाई-एंड-डाई हथकरघा शिल्प और प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है।
- यह नगर पश्चिमी ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण बुनाई केंद्रों में से एक है और वस्त्र उत्पादन पर निर्भर हजारों कारीगर परिवारों को आजीविका प्रदान करता है।
- संबलपुरी साड़ियाँ पारंपरिक “बंधा” टाई-एंड-डाई तकनीक के लिए जानी जाती हैं, जिसमें बुनाई से पहले धागों को रंगकर जटिल डिजाइन और आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- इन डिजाइनों में शंख, चक्र, फूल और जनजातीय परंपराओं से प्रेरित आकृतियाँ प्रमुख हैं, जो ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।
- बरपाली के हथकरघा उत्पादों को उनकी प्रामाणिकता और क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने के लिए “संबलपुरी बंधा टेक्सटाइल” के तहत भौगोलिक संकेतक (जीआई) मान्यता प्राप्त है।

- यह शिल्प पर्यावरण-अनुकूल बुनाई तकनीकों, आकर्षक रंगों और उत्कृष्ट कारीगरी के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ है।

स्थैतिक जीके

- ओडिशा की राजधानी — भुवनेश्वर
- बरगढ़ विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा उत्सव के लिए जाना जाता है।
- हीराकुंड बांध महानदी नदी पर संबलपुर जिले में स्थित है।

ओडिशा सरकार ने जून 2026 से सरकारी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया

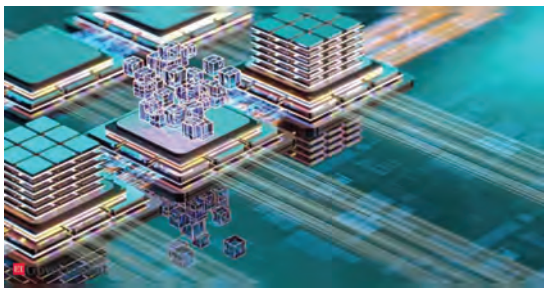


- ओडिशा सरकार ने 1 जून 2026 से सरकारी उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले सभी नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अनिवार्य कर दिया है।
- इस निर्णय का उद्देश्य हरित परिवहन को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और राज्य में सतत परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
- अब सरकारी विभाग आधिकारिक वाहन बेड़े के प्रतिस्थापन या विस्तार के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे।
- यह कदम ओडिशा की व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना और ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुरूप है।
- ओडिशा सरकार सब्सिडी, चार्जिंग अवसंरचना विस्तार और सार्वजनिक एवं निजी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से ईवी अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- राज्य सरकार ने प्रोत्साहन और सहायता तंत्र जारी रखने के लिए ओडिशा ईवी नीति 2021 की वैधता को 30 जून 2026 तक बढ़ाया था।
- ओडिशा वर्ष 2030–2036 तक नए वाहन पंजीकरणों में लगभग 50% ईवी अपनाने के लक्ष्य के साथ नई ईवी नीति 2025 पर भी कार्य कर रहा है।

स्थैतिक जीके

- ओडिशा की राजधानी – भुवनेश्वर
- वर्तमान मुख्यमंत्री – मोहन चरण माझी

भिवाड़ी में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्लस्टर का उद्घाटन किया गया



- राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का उद्घाटन मई 2026 में भिवाड़ी में भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया।
- भिवाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ।
- इस सेमीकंडक्टर क्लस्टर से क्षेत्र में लगभग 2,500 रोजगार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद जताई गई।
- इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान ने औपचारिक रूप से सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया।
- सेमीकंडक्टर्स को स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा प्रणालियों, एआई हार्डवेयर, दूरसंचार नेटवर्क और चिकित्सा उपकरणों के लिए आवश्यक घटक बताया गया।
- भिवाड़ी को उसकी मजबूत औद्योगिक अवसंरचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निकट होने के कारण चुना गया।
- यह पहल राजस्थान सरकार के “विकसित राजस्थान 2047” विजन को समर्थन प्रदान करती है।

सिक्किम ने 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम, 1909 लागू किया



- सिक्किम ने सिख समुदाय के लिए 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम, 1909 लागू करने की घोषणा की।
- सिक्किम में सिख दंपतियों को पारंपरिक आनंद कारज समारोह के तहत संपन्न विवाहों का अलग कानूनी ढाँचे में सीधे पंजीकरण करने की अनुमति दी गई।

- इससे पहले राज्य में अलग पंजीकरण नियमों के अभाव में कई सिख दंपति अपने विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत करते थे।
- केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सिक्किम में आनंद विवाह अधिनियम के लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
- यह लागू होना सिक्किम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2026 के निर्माण के बाद संभव हो सका।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में आनंद विवाह अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े प्रशासनिक अंतरालों को उजागर किया था।
- आनंद विवाह अधिनियम में वर्ष 2012 के संशोधन के बाद राज्यों को सिख विवाहों के लिए अलग विवाह पंजीकरण प्रणाली बनाने का अधिकार मिला था।
- आनंद कारज, जिसका अर्थ “आनंद का समारोह” है, सिखों का पारंपरिक विवाह संस्कार है, जो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है।
- आनंद कारज समारोह में सिख प्रार्थनाएँ और “लावां” कहलाने वाले चार वैवाहिक फेरे शामिल होते हैं।

पुरी, ओडिशा में निमापाड़ा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया



- निमापाड़ा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन 17 मई 2026 को ओडिशा के पुरी जिले के निमापाड़ा क्षेत्र में किया गया।
- इस उत्सव का उद्घाटन उत्कर्ष निमापाड़ा 2.0 पहल के तहत प्रभावती परिडा द्वारा किया गया।
- इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक विरासत, युवा सहभागिता, खेल गतिविधियाँ, जनजागरूकता अभियान और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का समावेश किया गया।
- उत्सव में स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, कलाकारों और युवा समूहों ने सक्रिय भागीदारी की।
- उत्सव के दौरान जनजातीय नृत्य, घोड़ा नृत्य, संकीर्तन, पाला और दशाकाठिया जैसी पारंपरिक ओडिया लोक प्रस्तुतियाँ प्रदर्शित की गईं।

- सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक और एकल अभिनय प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की गईं।
- पथ उत्सव का आयोजन एक सामुदायिक सड़क उत्सव के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य संस्कृति, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना था।

आंध्र प्रदेश ने बड़े परिवारों के लिए नकद प्रोत्साहन की घोषणा की



- एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
- यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई।
- राज्य सरकार एक महीने के भीतर इस योजना के विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश जारी करने वाली थी।
- प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर को ऐसी औसत बच्चों की संख्या बताया गया, जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, जिसे सामान्यतः प्रति महिला 2.1 बच्चे माना जाता है।
- लंबे समय तक घटती प्रजनन दर को जनसंख्या में कमी, वृद्ध आबादी, कार्यबल में गिरावट और आर्थिक चुनौतियों से जोड़ा गया।
- जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और चीन जैसे देशों का उदाहरण दिया गया, जो घटती जन्म दर के कारण जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- जनसंख्या में गिरावट को श्रमिकों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च, पेंशन बोझ में वृद्धि और धीमी आर्थिक वृद्धि से संबंधित बताया गया।



आरबीआई ने नियामकीय उल्लंघन पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार नियामकीय अनुपालन में विफलता के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया।
- आरबीआई ने जमाकर्ताओं के हित, प्रशासनिक कमियों और जनहित से जुड़े जोखिमों को इस निर्णय का प्रमुख कारण बताया।
- बैंक में बार-बार अनुपालन और परिचालन संबंधी विफलताएँ पाई गईं।
- आरबीआई ने कहा कि यह निर्णय पिछले कई वर्षों से चरणबद्ध तरीके से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बाद लिया गया है।
- **पहले लगाए गए प्रतिबंधों में शामिल थे:**
 - ◆ वर्ष 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध
 - ◆ वर्ष 2024 में नए जमा और क्रेडिट लेन-देन पर रोक
 - ◆ फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड जैसी सेवाओं पर प्रतिबंध
- लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक केवल मौजूदा ग्राहकों को अपनी जमा राशि निकालने की अनुमति दे सकेगा।
- आरबीआई बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा।
- बताया गया है कि बैंक के पास जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध है।

स्थैतिक बिंदु

- भारत में पेमेंट्स बैंकों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत लाइसेंस दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी।

सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड के नए दिशानिर्देश जारी किया



- सरकार ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) योजना की दूसरी किस्त के दिशानिर्देश जारी किए।
- इस योजना का उद्देश्य बेहतर शासन, निवेश वितरण और निगरानी तंत्र के माध्यम से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह की दक्षता बढ़ाना है।
- यह योजना सेबी-पंजीकृत श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से निवेश करेगी, जो आगे डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषण प्रदान करेंगे।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इस योजना की पहुँच और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एजेंसियों को भी शामिल करेगा।
- दिशानिर्देशों में एआईएफ को डीप-टेक फंड, माइक्रो वीसी फंड (प्रारंभिक चरण), विनिर्माण केंद्रित फंड और सेक्टर-एनॉस्टिक फंड के रूप में विभाजित किया गया है।
- योजना के तहत स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस और वेंचर कैपिटल निवेश समिति द्वारा मूल्यांकन की संरचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- समिति में वल्लभ भंसाली, अशोक झुनझुनवाला, रेणु स्वरूप, चिंतन वैष्णव और राजेश गोपीनाथन जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं।
- इस योजना से निजी निवेश को बढ़ावा मिलने और विभिन्न क्षेत्रों, चरणों तथा राज्यों के स्टार्टअप्स को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

स्थैतिक बिंदु

- सिडबी – स्थापना वर्ष 1990
- एआईएफ – सेबी द्वारा विनियमित निवेश कोष

मोबिक्विक् को एनबीएफसी लाइसेंस के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली



- वन मोबिक्विक् सिस्टम्स को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एनबीएफसी लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
- यह लाइसेंस कंपनी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मोबिक्विक् फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमएफएसपीएल) के माध्यम से ऋण संचालन शुरू करने की अनुमति देगा।
- संचालन की शुरुआत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करने और नियामकीय शर्तों को पूरा करने के बाद ही होगी।
- एनबीएफसी दर्जा मिलने के बाद मोबिक्विक् तीसरे पक्ष के ऋणदाताओं पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ऋण जारी और अंडरराइट कर सकेगा।
- इस कदम से कंपनी के लाभ मार्जिन में सुधार, जोखिम नियंत्रण में मजबूती और नए उत्पादों की लॉन्चिंग में तेजी आने की उम्मीद है।
- कंपनी उपभोक्ताओं और एमएसएमई को सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण प्रदान करने की योजना बना रही है, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III बाजारों में।
- मोबिक्विक् अपनी एआई/एमएल क्षमताओं और 18.6 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता आधार का उपयोग कर व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करेगा।
- मोबिक्विक् अब लेंडिंगकार्ड और कैपिटल प्लोट जैसी अन्य फिनटेक एनबीएफसी कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
- इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और यह 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

स्थैतिक बिंदु

- एनबीएफसी – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- आरबीआई – भारत में एनबीएफसी का नियामक संस्था

आरबीआई ने बेसल-III क्रेडिट जोखिम मानदंडों में संशोधन किया, अप्रैल 2027 से लागू होंगे



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बेसल-III के तहत क्रेडिट जोखिम पर पूंजी शुल्क (मानकीकृत दृष्टिकोण) से संबंधित अंतिम मानदंड जारी किए, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
- आरबीआई ने बिना रेटिंग वाली कॉरपोरेट और एनबीएफसी एक्सपोजर पर 150% जोखिम भार लागू करने की सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी है, जबकि पहले यह 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी।
- आरबीआई ने उन एक्सपोजर पर दंडात्मक प्रावधान हटा दिए हैं, जिन्हें पहले रेटिंग मिली थी लेकिन बाद में वे बिना रेटिंग वाले हो गए।
- बैंक एक्सपोजर के लिए आरबीआई ने एससीआरए आधारित ग्रेडिंग ढाँचे को समाप्त कर समान जोखिम भार लागू किए हैं:
 - ◆ दीर्घकालिक एक्सपोजर के लिए 100%
 - ◆ अल्पकालिक एक्सपोजर के लिए 50%
- भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएँ अब जोखिम भार की गणना के लिए मूल बैंक की बाहरी क्रेडिट रेटिंग का उपयोग कर सकेंगी।
- नियामकीय खुदरा एक्सपोजर ढाँचे का विस्तार कर 500 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यवसायों को भी शामिल किया गया है।
- खुदरा वर्गीकरण के तहत एक्सपोजर सीमा प्रति प्रतिपक्ष बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो पहले 7.5 करोड़ रुपये थी।
- विशेषीकृत ऋण श्रेणी में आरबीआई ने कमोडिटी फाइनेंस श्रेणी को हटा दिया है, जबकि परियोजना और वस्तु वित्त मौजूदा नियमों के तहत जारी रहेंगे।
- रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए मौजूदा जोखिम भार मानदंड बरकरार रखे गए हैं तथा पाँच वर्ष बाद संपत्ति मूल्यांकन संशोधन की अनुमति दी गई है।
- रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए न्यूनतम उधारकर्ता योगदान कुल परियोजना लागत का 25% निर्धारित किया गया है।

स्थैतिक बिंदु

- बेसल-III – वैश्विक बैंकिंग विनियमन ढाँचा
- जोखिम भार – पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक

शहरी सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने 'मिशन सक्षम' शुरू किया



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 'मिशन सक्षम' शुरू किया है।
- यह मिशन मोड में संचालित देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को बेहतर बनाना है।
- इस पहल का मुख्य फोकस बेहतर अनुपालन संस्कृति, जोखिम प्रबंधन और शहरी सहकारी बैंकों की संस्थागत मजबूती पर है।
- आरबीआई ऑफलाइन सत्रों और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- इस पहल का लक्ष्य बोर्ड सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और जोखिम प्रमुखों सहित लगभग 1.4 करोड़ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देना है।
- प्रशिक्षण सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अधिक लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए आत्मनिर्भर व्यवस्था विकसित करना है।

स्थैतिक बिंदु

- यूसीबी – शहरी सहकारी बैंक
- आरबीआई – भारत का शीर्ष बैंकिंग नियामक संस्था

निष्क्रिय पीएफ खातों को सक्रिय करने के लिए ईपीएफओ लाएगा आधार आधारित पोर्टल



- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निष्क्रिय पीएफ खातों तक पहुँच के लिए ई-प्राप्ति (ईपीएफ आधार आधारित एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स) पोर्टल शुरू करेगा।
- इस पोर्टल का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय या बिना दावा किए गए ईपीएफ खातों का पता लगाने, उन्हें एक्सेस करने और पुनः सक्रिय करने में सहायता प्रदान करना है।
- यह विशेष रूप से उन सदस्यों के लिए उपयोगी होगा जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) नहीं है या जिनके पुराने भौतिक ईपीएफ खाते हैं।
- यह प्रणाली सुरक्षित और सहज पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करेगी।
- उपयोगकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से पुराने खातों की पहचान कर सकेंगे, प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे और उन्हें यूएन से जोड़ सकेंगे।
- यह पहल लंबे समय से लंबित बिना दावा किए गए भविष्य निधि जमा की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य ईपीएफ सेवाओं में पहुँच और दक्षता को बेहतर बनाना है।
- इस कदम से सेवानिवृत्ति बचत प्रबंधन में वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

स्थैतिक बिंदु

- ईपीएफओ – श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था
- यूएन – यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

आरबीआई ने ऑटो-डेबिट नियमों में बदलाव किया



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड, यूपीआई और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के माध्यम से होने वाले आवर्ती डिजिटल भुगतानों के लिए ई-मैडेट ढाँचे को अपडेट किया।
- अब 15,000 रुपये तक के आवर्ती लेन-देन एक बार अतिरिक्त प्रमाणीकरण (एएफए) के साथ ई-मैडेट पंजीकरण के बाद बिना ओटीपी के पूरे किए जा सकेंगे।
- इसमें ईएमआई, एसआईपी, सब्सक्रिप्शन, उपयोगिता बिल, बीमा और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
- बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल के लिए ई-मैडेट के तहत पंजीकरण होने पर बिना बार-बार ओटीपी के 1 लाख रुपये तक की सीमा की अनुमति दी गई है।

- ग्राहक एएफए प्रमाणीकरण के माध्यम से किसी भी समय अपने मैडेट में संशोधन, रोक या रद्द कर सकते हैं।
- बैंकों को डेबिट से कम-से-कम 24 घंटे पहले राशि, तिथि और व्यापारी विवरण सहित प्री-डेबिट अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा।
- ई-मैडेट सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- ग्राहकों को अलर्ट प्राप्त करने का माध्यम (एसएमएस, ईमेल आदि) चुनने की सुविधा भी दी गई है।
- अनधिकृत ई-मैडेट लेन-देन पर समय पर शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में ग्राहकों को शून्य देयता सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- फास्टैग और एनसीएमसी ऑटो-रिचार्ज लेन-देन के लिए प्री-डेबिट अलर्ट अनिवार्य नहीं होगा।
- आरबीआई ने गिफ्ट, ट्रांजिट और एनआरआई पीपीआई जैसी श्रेणियों सहित डिजिटल वॉलेट (पीपीआई) के लिए नए मानदंड भी प्रस्तावित किए हैं।

जीडीपी आंकड़े जारी करने की तारीख हर वर्ष 7 जून तय की गई



- सरकार ने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनंतिम अनुमान और चौथी तिमाही के जीडीपी अनुमानों की जारी करने की तारीख में बदलाव किया है।
- अब ये आंकड़े हर वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 7 जून को जारी किए जाएंगे।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि यदि 7 जून अवकाश होगा, तो अनंतिम अनुमान उससे पहले के कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति से परामर्श के बाद इस जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।
- मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव डेटा की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
- मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन राष्ट्रीय खातों के संकलन में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता, कवरेज और विश्वसनीयता में सुधार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

भारत ने सोना और चांदी आयात शुल्क बढ़ाकर 15% किया



- भारत ने 13 मई 2026 को सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को पहले के 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया।
- नई शुल्क संरचना में बहुमूल्य धातुओं के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर शामिल किया गया।
- यह नया शुल्क सोना, चांदी, ज्वेलरी फाइंडिंग्स और संबंधित औद्योगिक आयातों पर सीमा शुल्क वर्गीकरण नियमों के तहत लागू किया गया।
- वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात 24% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- सोना, कच्चे तेल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयातित उत्पाद बन गया और कुल आयात बिल में इसकी हिस्सेदारी लगभग 9% रही।
- संयुक्त अरब अमीरात कुछ विशेष सोना खेपों के लिए भारत की कोटा-आधारित आयात व्यवस्था का हिस्सा बना रहा।
- आयात शुल्क वृद्धि को विदेशी मुद्रा प्रबंधन संबंधी चिंताओं और बढ़ते सोना आयात को नियंत्रित करने के प्रयासों से जोड़ा गया।
- उच्च आयात शुल्क को भारत में सोने की तस्करी की लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों से भी संबंधित माना गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए बढ़ी हुई एमएसपी को मंजूरी दी



- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी।
- यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया।
- संशोधित एमएसपी पैकेज का किसानों की खरीद सहायता पर अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये रहा।

- सरकार की खरीद प्रणाली के तहत खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों सहित 22 अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया गया।
- सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि सूरजमुखी बीज के लिए दर्ज की गई, इसके बाद कपास, रामतिल और तिल का स्थान रहा।
- धान के एमएसपी में संशोधन करते हुए सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।
- एमएसपी ढाँचा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट से लागू 1.5 गुना उत्पादन लागत के फार्मूले पर आधारित रहा।
- उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभांश मूंग में 61% दर्ज किया गया, इसके बाद मक्का और बाजरा 56% तथा अरहर 54% पर रहे।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत में प्रमुख आर्थिक और कृषि मूल्य नीतियों के लिए प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था बनी रही।

भारत-यूई व्यापार साझेदारी ने 100 अरब डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया



- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 100 अरब अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते आर्थिक संबंधों को बल मिला है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत-यूई द्विपक्षीय व्यापार लगभग 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 100.03 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- इस वृद्धि का प्रमुख कारण कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) रहा, जो 1 मई 2022 से लागू हुआ था।
- व्यापार विस्तार में रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद और कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
- दोनों देशों ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- यूई वर्तमान में भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और भारत को कच्चा तेल, एलएनजी तथा एलपीजी आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बना हुआ है।
- आईएनआर और आईडी आधारित लोकल करेंसी सेटलमेंट प्रणाली से द्विपक्षीय लेन-देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।

स्थैतिक जीके

- सीईपीए का पूर्ण रूप – कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिस पर भारत और यूई ने फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए थे।
- यूई की राजधानी – अबू धाबी
- यूई की मुद्रा – यूई दिरहम
- यूई के राष्ट्रपति – शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु इन-स्पेस ने पीएसएलवी तकनीक हस्तांतरण शुरू किया



- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) की पूर्ण तकनीक हस्तांतरण प्रक्रिया हेतु भारतीय उद्योगों से आवेदन आमंत्रित किए।
- इस पहल का उद्देश्य निजी कंपनियों को भविष्य में स्वतंत्र रूप से पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण, एकीकरण, स्वामित्व और व्यावसायिक प्रक्षेपण करने में सक्षम बनाना है।
- इन-स्पेस ने पात्र भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं और औद्योगिक समूहों से भागीदारी के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटेरेस्ट (ईओआई) जारी किया।
- तकनीक हस्तांतरण में डिजाइन दस्तावेज, निर्माण तकनीक, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली, परीक्षण प्रक्रियाएँ और प्रक्षेपण संचालन सहायता शामिल हैं।
- पीएसएलवी को विश्व के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहनों में माना जाता है और इसने भारत तथा विदेशी देशों के सैकड़ों उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए हैं।
- यह कदम भारत के व्यापक अंतरिक्ष सुधारों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और घरेलू अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है।
- इन-स्पेस इस प्रक्रिया के दौरान उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन, सहयोग और प्राधिकरण सहायता प्रदान करेगा।

स्थैतिक जीके

- इन-स्पेस की स्थापना वर्ष 2020 में भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की गई थी।

- पीएसएलवी का पहला सफल प्रक्षेपण वर्ष 1994 में हुआ था।
- इसके प्रमुख मिशनों में मंगल ऑर्बिटर मिशन और वर्ष 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी



- भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। यह केंद्रीय बैंक द्वारा अब तक का सबसे बड़ा लाभांश भुगतान है। यह निर्णय आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक में लिया गया।
- अधिशेष हस्तांतरण को संशोधित आर्थिक पूंजी ढाँचे (ईसीएफ) के तहत अंतिम रूप दिया गया, जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए जोखिम प्रावधानों और अतिरिक्त पूंजी के उस स्तर को निर्धारित करता है जिसे सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों से बढ़ी ब्याज आय और प्रभावी तरलता संचालन ने वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई की आय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया।
- यह हस्तांतरण सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने, उधारी के दबाव को कम करने तथा अवसंरचना विकास और कल्याणकारी व्यय के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा।



स्काईरूट का विक्रम-1 बना भारत का पहला निजी रॉकेट



- ए. रेवंत रेड्डी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट के फ्लाइट हार्डवेयर को खाना किया।
- विक्रम-1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है।
- इस रॉकेट को प्रक्षेपण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया है।
- स्काईरूट आने वाले महीनों में अपना पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
- रॉकेट का पूर्ण डिजाइन और विकास हैदराबाद में किया गया है।
- स्काईरूट ने इससे पहले वर्ष 2022 में अपना पहला सब-ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था।
- तेलंगाना बोइंग, एयरबस और सफ्रान जैसी कंपनियों की मौजूदगी के साथ एक प्रमुख एयरोस्पेस केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- तेलंगाना में इंजीनियरिंग निर्यात में वर्ष 2023-24 से 2024-25 के बीच 117.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- सरकार वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से एयरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

स्थैतिक बिंदु

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का संचालन करता है।
- हैदराबाद भारत का प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र है।

एनआईटी राउरकेला ने मसालों में मिलावट पकड़ने की एआई तकनीक विकसित की

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) राउरकेला ने मसालों और खाद्य पदार्थों में मिलावट का कुछ ही सेकंड में पता लगाने वाली एआई आधारित तकनीक विकसित कर उसका पेटेंट कराया है।



- यह नवाचार मिलावटी पदार्थों की त्वरित पहचान और मात्रा निर्धारण में सक्षम है, जिससे खाद्य सुरक्षा जांच की सटीकता और दक्षता में सुधार होगा।
- आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य मिलावट और प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह तकनीक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- मुंबई की एक दुखद घटना के बाद इस तकनीक ने विशेष ध्यान आकर्षित किया, जहाँ संदिग्ध दूषित भोजन के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे वर्तमान निगरानी प्रणाली की कमियाँ उजागर हुई थीं।
- यह प्रणाली पारंपरिक और समय लेने वाली प्रयोगशाला जांच पद्धतियों की तुलना में तेज, विश्वसनीय और बड़े स्तर पर उपयोग योग्य समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- इससे भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन, गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
- यह नवाचार देशभर में सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत स्क्रीनिंग तकनीकों की आवश्यकता को भी समर्थन देता है।

स्थैतिक बिंदु

- एनआईटी राउरकेला – स्थापना वर्ष 1961
- खाद्य सुरक्षा – एफएसएसआई द्वारा विनियमित

डब्ल्यूएचओ ने शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आर्टेमिथर-ल्यूमेफेन्ट्रिन को प्री-क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है, जो नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित पहली मलेरिया दवा है।
- यह मंजूरी पुष्टि करती है कि यह दवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है, जिससे इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपयोग संभव होगा।



- इससे पहले शिशुओं का उपचार वयस्कों या बड़े बच्चों की दवाओं से किया जाता था, जिससे खुराक संबंधी त्रुटियों, दुष्प्रभावों और विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता था।
- नई दवा मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर अफ्रीका में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले लगभग 3 करोड़ बच्चों के उपचार संबंधी बड़ी कमी को दूर करने में मदद करेगी।
- मलेरिया अब भी एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। वर्ष 2024 में इसके 28.2 करोड़ मामले और 6.10 लाख मौतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश अफ्रीका में हुईं।
- पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मलेरिया से होने वाली मौतों की हिस्सेदारी लगभग 75% है, जो शिशुओं के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता को दर्शाती है।
- डब्ल्यूएचओ ने कहा कि टीकों, जांच सुविधाओं, मच्छरदानियों और दवाओं के माध्यम से प्रगति हुई है, लेकिन दवा प्रतिरोध और वित्तीय कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।
- यह प्री-क्वालिफिकेशन सार्वजनिक क्षेत्र में खरीद और वैश्विक वितरण को समर्थन देगा, जिससे निम्न आय वाले देशों में दवा की उपलब्धता बेहतर होगी।

स्थैतिक बिंदु

- मलेरिया – मच्छरों से फैलने वाला रोग
- डब्ल्यूएचओ – स्थापना वर्ष 1948

भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सीआई ने 'मिशन दृष्टि' लॉन्च किया



- गैलेक्सीआई ने अमेरिका से फाल्कन-9 रॉकेट के माध्यम से दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह 'मिशन दृष्टि' लॉन्च किया।
- 190 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- ऑप्टोसार तकनीक ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपचर रडार (एसएआर) को मिलाकर हर मौसम और दिन-रात पृथ्वी अवलोकन की सुविधा प्रदान करती है।
- यह मिशन निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत करेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सी. पी. राधाकृष्णन ने इस प्रक्षेपण को भारत के अंतरिक्ष नवाचार तंत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
- यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी स्टार्टअप्स और युवा आधारित नवाचार की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

स्थैतिक बिंदु

- एसएआर (सिंथेटिक अपचर रडार) बादलों और रात में भी इमेजिंग करने में सक्षम है।
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का विनियमन इन-स्पेस द्वारा किया जाता है तथा निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वीडन भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन 'शुक्रयान' में शामिल हुआ



- स्वीडन वैज्ञानिक सहयोग समझौते के तहत भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन, जिसे 'शुक्रयान' भी कहा जाता है, में शामिल हुआ।
- भारत का शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अंतरग्रहीय मिशन के रूप में नियोजित किया गया था।
- स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने मिशन के लिए "वीनसियन न्यूट्रल्स एनालाइज़र" (वीएनए) पेलोड विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
- वीनसियन न्यूट्रल्स एनालाइज़र को सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल तथा बाह्यमंडल के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 में 1,236 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी थी।

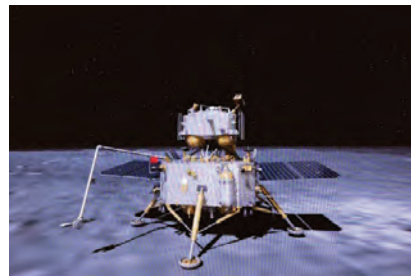
- इस अंतरिक्ष यान को भारत के भारी प्रक्षेपण वाहन एलवीएम-3 के माध्यम से प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई थी।
- ऑर्बिटर को शुक्र ग्रह के वायुमंडल, बाह्यमंडल, ज्वालामुखीय सतह, मौसम प्रणालियों और तीव्र गति से घूमने वाले बादलों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था।

स्थैतिक बिंदु

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत शुक्रयान मिशन का नेतृत्व कर रहा है।
- शुक्र ग्रह को पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान के कारण “पृथ्वी का जुड़वाँ” कहा जाता है।
- शुक्र ग्रह अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल और 460°C से अधिक सतही तापमान के लिए प्रसिद्ध है।
- अंतरिक्ष यान के लगभग 112 दिनों की यात्रा के बाद जुलाई 2028 तक शुक्र ग्रह पहुँचने की उम्मीद जताई गई थी।

चीन ने दक्षिणी ध्रुव अनुसंधान के लिए चांग'ई-7 चंद्र मिशन की योजना बनाई

- चीन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में चांग'ई-7 चंद्र मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है।
- यह मिशन ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और चंद्र अन्वेषण के लिए एक छोटे उछलने वाले अंतरिक्ष यान से युक्त होगा।



- चांग'ई-7 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थायी रूप से अंधकारमय क्षेत्रों में जल-बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों की खोज करना है।
- शैकलटन क्रेटर के किनारे को इस मिशन के लिए संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में चुना गया है।
- चीन ने वर्ष 2028-29 के लिए चांग'ई-8 मिशन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव अनुसंधान जारी रखना और चंद्र मिट्टी से 3डी प्रिंटिंग सहित इन-सीटू संसाधन उपयोग तकनीकों का परीक्षण करना है।
- चांग'ई-8 मिशन में पाकिस्तान के चंद्र रोवर और तुर्किये के अन्वेषण रोवर सहित अंतरराष्ट्रीय पेलोड शामिल किए जाने की संभावना है।
- चीन के दीर्घकालिक चंद्र कार्यक्रम में वर्ष 2031 से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की योजना भी शामिल है।
- चीन ने वर्ष 2030 तक प्रारंभिक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' का 7वां संस्करण संपन्न



- भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' का 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के नमंगन में संपन्न हुआ।
- यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद-रोधी अभियानों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- इस अभ्यास में दोनों देशों के 60-60 सैनिकों सहित कुल 120 सैन्यकर्मियों ने भाग लिया, जो संतुलित भागीदारी को दर्शाता है।
- भारतीय दल में सेना के 45 और वायुसेना के 15 जवान शामिल थे, जबकि उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसकी सेना और वायुसेना ने किया।
- अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में समन्वय, सामरिक कौशल और परिचालन तैयारियों को बेहतर बनाना था।
- इसमें संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास, अर्ध-पहाड़ी युद्ध और रणनीति एवं प्रक्रियाओं से जुड़ी सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान दिया गया।
- अभ्यास में कमांड एवं नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने तथा सैन्य अंतरसंचालन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
- यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को दर्शाता है।

स्थैतिक बिंदु

- उज्बेकिस्तान की राजधानी – ताशकंद
- दुस्तलिक – भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास

डीआरडीओ और नौसेना ने लघु दूरी नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया

- डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (एनएसएसएम-एसआर) का पहला सफल सल्वो परीक्षण किया।



- परीक्षण के दौरान एक ही नौसैनिक हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से कम समय अंतराल में दो एनएसएसएम-एसआर मिसाइलें दागी गईं।
- मिसाइल ने सफलतापूर्वक जलरेखा लक्ष्य भेदन क्षमता और उन्नत सल्वो लॉन्च क्षमता का प्रदर्शन किया।
- एनएसएसएम-एसआर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें उन्नत नेविगेशन, मार्गदर्शन, सीकर और फाइबर-ऑप्टिक जाइरोस्कोप आधारित प्रणालियाँ शामिल हैं।
- इस मिसाइल प्रणाली का विकास हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया है।
- चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) ने रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणालियों के माध्यम से मिसाइल परीक्षण की निगरानी की।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल मिसाइल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग साझेदारों को बधाई दी।

भारत की लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के करीब पहुंची: डीआरडीओ



- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (एलआर-एसएसएम) कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसके प्रारंभिक परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है।

- यह जानकारी समीर वी. कामत ने एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 के दौरान दी।
- एलआर-एसएचएम भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा आवश्यकताओं के लिए विकसित हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल (एचजीवी) है।
- यह स्वदेशी एवियोनिक्स और सेंसर की मदद से स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर अत्यधिक सटीकता के साथ प्रहार करने में सक्षम है।
- यह मिसाइल मैक-10 तक की गति प्राप्त कर सकती है और ग्लाइड युद्धाभ्यास के साथ अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन करती है।
- इसमें निम्न-ऊँचाई उड़ान, उच्च गतिशीलता और स्टीलथ क्षमता जैसी विशेषताएँ हैं, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- मिसाइल में दो-चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसके बाद लक्ष्य पर प्रहार से पहले बिना शक्ति वाला ग्लाइड चरण आता है।
- यह भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक प्रहार क्षमता में प्रगति को दर्शाता है।
- डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज दोनों प्रकार की मिसाइलों पर कार्य कर रहा है, जिनमें ग्लाइड संस्करण फिलहाल अधिक उन्नत माना जा रहा है।

रक्षा-तकनीक स्टार्टअप आर्मरी को रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपये के अनुबंध मिला



- आर्मरी को रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपये के तीन अनुबंध प्राप्त हुए।
- ये अनुबंध एआई आधारित काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सी-यूएस) 'सर्ज' की आपूर्ति के लिए दिए गए हैं।
- इन प्रणालियों को दुश्मन ड्रोन का पता लगाने, उनकी निगरानी करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी।
- यह समझौता स्वदेशी रक्षा तकनीक और स्टार्टअप भागीदारी पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।
- संस्थापक अमरदीप सिंह ने कहा कि ऐसे आदेश नवाचार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं।
- बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए, जो पिछले वर्ष के 6.81 ट्रिलियन रुपये और वित्त वर्ष 2025 के 6.22 ट्रिलियन रुपये से अधिक है।

- रक्षा बजट में यह वृद्धि आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन प्रदान करती है।

स्थैतिक बिंदु

- सी-यूएस – ड्रोन की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने वाली तकनीक
- भारत iDEX (इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) जैसी पहलों के माध्यम से रक्षा नवाचार को बढ़ावा देता है।

भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया



- भारत ने ओडिशा तट से स्वदेशी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे उसकी समुद्री प्रहार क्षमता और मजबूत हुई।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1,500 किलोमीटर है।
- यह परीक्षण चरण-द्वितीय उड़ान परीक्षण के रूप में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- मिसाइल ने सफल प्रक्षेपण, चरण पृथक्करण और विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से ट्रैकिंग का सफल प्रदर्शन किया।
- अत्यधिक गति से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए विकसित यह मिसाइल वैश्विक समुद्री तनावों के बीच भारत की नौसैनिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है।
- सशस्त्र बलों में अंतिम शामिल किए जाने से पहले इसके और परीक्षण किए जाने की योजना है।
- यह विकास स्वदेशी रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भरता पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

स्थैतिक बिंदु

- हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक-5 से अधिक गति से चलती हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें रोकना कठिन होता है।
- डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है।

डीआरडीओ ने हैदराबाद में लंबी अवधि वाले स्क्रेमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया



- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल-स्केल स्क्रेमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि वाला सफल परीक्षण किया।
- इस परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन-टाइम हासिल किया गया, जो जनवरी 2026 में किए गए 700 सेकंड के पिछले परीक्षण से अधिक था।
- इस उपलब्धि से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिली।
- परीक्षण ने कंबस्टर डिजाइन और परीक्षण सुविधा की उन्नत क्षमताओं दोनों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया।
- इस कंबस्टर का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदारों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से किया।
- यह प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन का उपयोग करती है।
- इसमें उन्नत थर्मल बैरियर कोटिंग और आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का भी उपयोग किया गया है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की सराहना करते हुए इसे भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं के लिए मजबूत आधार बताया।
- यह सफल परीक्षण उन्नत एयरोस्पेस और अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है।

स्थैतिक बिंदु

- डीआरडीओ की स्थापना – 1958
- स्क्रेमजेट का पूर्ण रूप – सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट

टाटा ने पहला भारत में निर्मित C-295 विमान पेश किया



- भारत ने गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा-एयरबस सुविधा केंद्र से पहले निजी क्षेत्र में निर्मित सैन्य विमान एयरबस C-295 के रोलआउट के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की।
- इस विमान का निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए 21,935 करोड़ रुपये के C-295 कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।
- भारत ने वर्ष 2021 में 56 C-295 परिवहन विमानों के लिए समझौता किया था। इनमें से 16 विमान सीधे स्पेन से आपूर्ति किए जा रहे हैं, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जा रहा है।
- वडोदरा संयंत्र भारत का पहला निजी क्षेत्र आधारित फाइनल असेंबली लाइन (FAL) केंद्र है, जहाँ सैन्य विमानों का निर्माण किया जा रहा है।
- C-295 विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एब्रो बेड़े का स्थान लेगा और “मेक इन इंडिया” तथा “आत्मनिर्भर भारत” पहल को मजबूती देगा।
- यह विमान सैनिक परिवहन, माल ढुलाई, चिकित्सीय निकासी और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- भारत में निर्मित विमानों के लगभग 85% संरचनात्मक निर्माण कार्य घरेलू स्तर पर भारतीय एमएसएमई और आपूर्तिकर्ताओं के सहयोग से किए जाएंगे।

अतिरिक्त जानकारी

- गुजरात के मुख्यमंत्री – भूपेंद्र पटेल
- भारत के रक्षा मंत्री – राजनाथ सिंह
- एयरबस मुख्यालय – टूलूज़, फ्रांस

डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ‘तारा’ ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया



- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने 7 मई 2026 को ओडिशा तट के पास टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (तारा) हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पहले उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, आईएएफ, डीसीपीपी और उद्योगों को बधाई दी। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

- तारा भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो बिना निर्देशित वारहेड को सटीक निर्देशित हथियार में बदलती है। इसका डिजाइन और विकास हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत तथा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है।
- यह स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली पहली ऐसी प्रणाली है, जिसमें अत्याधुनिक कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग किया गया है, ताकि कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ाकर जमीनी लक्ष्यों को नष्ट किया जा सके।
- इस किट का विकास डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर्स और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है, जिन्होंने इसके उत्पादन कार्य भी शुरू कर दिए हैं।

डीआरडीओ ने स्वदेशी यूएलपीजीएम-वी3 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया



- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी यूएलपीजीएम-वी3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे भारत की सटीक प्रहार और रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिली।
- यूएलपीजीएम का पूर्ण रूप “अल्ट्रा लाइट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल” है, जिसे मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), हेलीकॉप्टरों और हल्के हवाई प्लेटफॉर्म से तैनात करने के लिए विकसित किया गया है।
- इस मिसाइल को हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों, बंकरों, वाहनों और दुश्मन के ठिकानों को अत्यधिक सटीकता तथा न्यूनतम सहायक क्षति के साथ निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है।

- बताया गया कि वी3 संस्करण में उन्नत ड्यूल-चैनल सीकर, बेहतर लक्ष्य निर्धारण क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधी उपायों के खिलाफ अधिक सुरक्षा क्षमता शामिल है।

स्थैतिक जीके

- डीआरडीओ की स्थापना – वर्ष 1958
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- वर्तमान डीआरडीओ अध्यक्ष – समीर वी. कामत
- भारत के एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने किया था।

मेघालय में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ



- प्रगति 2026 का आयोजन 20 मई 2026 को उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ।
- भारत ने इस अभ्यास में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम और फिलीपींस सहित 12 साझेदार देशों के सशस्त्र बल कर्मियों की मेजबानी की।
- यह अभ्यास जंगल और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थितियों में संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित रहा।
- प्रगति 2026 का उद्देश्य भाग लेने वाले सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता, समन्वय और पेशेवर सहयोग को बेहतर बनाना था।
- अभ्यास के दौरान आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
- मेघालय को पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में से एक तथा जंगल युद्ध प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया।



अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गोवर्धन दास सदस्य नियुक्त: रिपोर्ट



- अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है।
- वैज्ञानिक गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाए जाने की उम्मीद है।
- अशोक लाहिड़ी भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं।
- वह 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
- गोवर्धन दास वर्तमान में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल के निदेशक हैं।
- उन्होंने पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कार्य किया था तथा स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अध्यक्ष भी रहे हैं।

स्थैतिक बिंदु

- नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
- नीति आयोग की प्रमुख भूमिकाओं में नीति निर्माण, सहकारी संघवाद और दीर्घकालिक विकास योजना शामिल हैं।

विक्रम दाराईस्वामी ब्रिटेन कार्यकाल के बाद चीन में भारत के राजदूत नियुक्त



- विक्रम दाराईस्वामी ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और उन्हें चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
- ब्रिटेन में अपने तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने में योगदान शामिल रहा।
- इंडो-पैसिफिक मामलों की ब्रिटिश मंत्री सीमा मल्होत्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की सराहना की।
- उन्होंने निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए यूके-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जैसी पहलों को भी समर्थन दिया।
- उनके कूटनीतिक कार्यों को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है।

संजय जमुआर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले सीईओ नियुक्त



- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (डीएमआईएल) का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
- डीएमआईएल, डीएमआरसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विदेशी शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के लिए बोली लगाने और वैश्विक परामर्श सेवाओं का विस्तार करने हेतु हाल ही में स्थापित किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य मेट्रो योजना, निर्माण और संचालन में डीएमआरसी की विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है।
- संजय जमुआर को भारतीय रेलवे, डीएमआरसी तथा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और पश्चिम एशिया जैसे वैश्विक बाजारों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।
- वर्ष 1998 में वह डीएमआरसी के पहले संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) कर्मचारी थे, जिससे उनकी यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

- डीएमआरसी पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और बांग्लादेश की ढाका मेट्रो परियोजना के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- इसके अलावा, डीएमआरसी चेन्नई, मुंबई और पटना मेट्रो प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव अनुबंधों का प्रबंधन कर रहा है तथा देश की कई प्रमुख मेट्रो परियोजनाओं में परामर्श भूमिका निभा रहा है।
- डीएमआईएल भारत और विदेशों में मेट्रो परियोजनाओं की बोली और संचालन एवं रखरखाव कार्यों के माध्यम से डीएमआरसी की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

स्थैतिक बिंदु

- डीएमआरसी – स्थापना वर्ष 1995
- आईआरटीएस – भारतीय रेलवे यातायात सेवा

रोहित जैन भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर नियुक्त



- रोहित जैन ने तीन वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- इससे पहले वह आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे और 34 वर्षों से अधिक अनुभव वाले करियर केंद्रीय बैंकर हैं। उन्होंने वर्ष 1991 में आरबीआई से जुड़ाव किया था।
- वह बाह्य निवेश, वित्तीय बाजार विनियमन, आंतरिक ऋण प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, फिनटेक, जोखिम निगरानी, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी एवं बैंक खाते, कॉर्पोरेट रणनीति और राजभाषा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- उनकी व्यापक जिम्मेदारियाँ वित्तीय बाजारों, विदेशी मुद्रा संचालन और डिजिटल वित्त विनियमन के प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं।
- उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एम.कॉम की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही उनके पास सीएआईआईबी और जीएआरपी जैसी पेशेवर प्रमाणिकताएँ भी हैं।

विश्वजीत सहाय ने रक्षा मंत्रालय में सचिव (रक्षा वित्त) का पदभार संभाला

- विश्वजीत सहाय ने रक्षा मंत्रालय में सचिव (रक्षा वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया।



- वह रक्षा वित्तीय प्रशासन और रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- इससे पहले वह इसी मंत्रालय में रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के पद पर कार्यरत थे।
- वर्ष 1990 बैच के आईडीएएस अधिकारी विश्वजीत सहाय के पास रक्षा वित्त और लोक प्रशासन का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
- उन्होंने अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग), संयुक्त सचिव (भारी उद्योग) तथा रक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
- रक्षा लेखा विभाग में उन्होंने प्रयागराज में पीसीडीए (पेंशन) और संयुक्त/विशेष सीजीडीए के रूप में भी सेवाएँ दी हैं।
- उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है तथा विधि की डिग्री भी हासिल की है, जो उनके मजबूत प्रशासनिक अनुभव को दर्शाती है।

स्थैतिक बिंदु

- सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मामलों में बजट, व्यय और वित्तीय सलाह से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।
- भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) सशस्त्र बलों के वित्तीय प्रशासन का प्रबंधन करती है।

कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए



- कुमार मंगलम बिड़ला को 5 मई 2026 से वोडाफोन आइडिया का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- उन्होंने रविंदर टक्कर का स्थान लिया, जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वे गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में जुड़े रहेंगे।
- बिड़ला इससे पहले वर्ष 2018 से 2021 तक कंपनी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्ष 2023 में पुनः बोर्ड में शामिल हुए थे।
- यह नेतृत्व परिवर्तन सरकार द्वारा एजीआर बकाया में 27% की कमी कर उसे 64,046 करोड़ रुपये करने के बाद हुआ, जिससे कंपनी पर वित्तीय दबाव कम हुआ।
- वोडाफोन आइडिया ने अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये ऋण और 10,000 करोड़ रुपये गैर-वित्तपोषित राशि शामिल है।
- कंपनी का लक्ष्य नेटवर्क विस्तार, लाभप्रदता में सुधार और तीव्र दूरसंचार प्रतिस्पर्धा के बीच ग्राहकों को बनाए रखना है।

सेबी ने संजय शौरी और वायरल मोदी को एनएसई के कार्यकारी निदेशक पद के लिए मंजूरी दी



- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में दो कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति को मंजूरी दी।
- ये नियुक्तियाँ सेबी के उस निर्देश के बाद की गईं, जिसमें बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) को प्रमुख परिचालन और नियामकीय कार्यों के लिए कम-से-कम दो कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने को कहा गया था।
- वायरल मोदी को महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया, जबकि संजय शौरी को नियमन, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक शिकायतों से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई।
- वायरल मोदी इससे पहले एनएसई में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जबकि संजय शौरी कॉर्पोरेट कार्य महानिदेशक के पद पर रहे हैं।
- इन नियुक्तियों की अवधि पाँच वर्ष होगी और दोनों कार्यकारी निदेशक एनएसई के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।
- इस कदम का उद्देश्य बाजार संस्थानों में प्रशासन, परिचालन दक्षता, अनुपालन और निवेशक संरक्षण को मजबूत करना है।

स्थैतिक बिंदु

- सेबी भारत के प्रतिभूति और पूंजी बाजार का नियामक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी।

अंबाती रायडू एचसीए के क्रिकेट संचालन निदेशक नियुक्त हुए



- अंबाती रायडू को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) का क्रिकेट संचालन निदेशक नियुक्त किया गया।
- उनका तीन वर्षीय कार्यकाल तत्काल प्रभाव से शुरू हुआ, जिसमें हैदराबाद में क्रिकेट प्रशासन और खिलाड़ी विकास को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी शामिल है।
- रायडू के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल का व्यापक अनुभव है।
- उन्होंने भारत के लिए 55 वनडे और 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, साथ ही 97 प्रथम श्रेणी मैचों में भी भाग लिया है।
- रायडू मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए छह आईपीएल खिताब जीत चुके हैं।
- उनकी नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने वर्ष 2019 में एचसीए पर कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप वाले चयन को लेकर आलोचना की थी।
- हैदराबाद क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने आंध्र और बड़ौदा के लिए घरेलू क्रिकेट खेला, जिसके बाद संन्यास लिया।
- संन्यास के बाद उन्होंने सीपीएल और आईएलटी20 जैसी लीगों में भी हिस्सा लिया।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया



- एन. एस. राजा सुब्रमणि को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया गया है।

- वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।
- उन्होंने अनिल चौहान का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।
- लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।
- इससे पहले वह जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख के पद पर रहे।
- उन्होंने वर्ष 2023 से 2024 तक जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), सेंट्रल कमांड का पद भी संभाला।

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया



- कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख (सीएनएस) नियुक्त किया गया है।
- वह दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
- वाइस एडमिरल स्वामीनाथन जुलाई 2025 से पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे।
- 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करने वाले स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला के विशेषज्ञ हैं।
- उन्होंने आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिश, आईएनएस मैसूर और आईएनएस विक्रमादित्य सहित कई प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म का नेतृत्व किया है।
- इससे पहले वह नौसेना उप प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और कार्मिक, प्रशिक्षण तथा फ्लीट संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
- उन्होंने परिचालन सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना सुरक्षा दल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम), अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) और विशिष्ट सेवा मेडल (वीएसएम) से सम्मानित किया जा चुका है।

वाइस एडमिरल संजय वात्सायन नए पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख नियुक्त किए गए



- संजय वात्सायन को पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसी-इन-सी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- वह वर्तमान में नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
- पश्चिमी नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- वाइस एडमिरल वात्सायन को वर्ष 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ था।
- वह गनरी और मिसाइल प्रणाली के विशेषज्ञ हैं।
- अपने नौसैनिक करियर के दौरान उन्होंने मिसाइल नौकाओं, मिसाइल कॉर्वेट और निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट का नेतृत्व किया है।
- उन्होंने नौसेना मुख्यालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ में परिचालन, नीति और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।
- उन्हें वर्ष 2021 में विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया था।

स्थैतिक बिंदु

- पश्चिमी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की तीन प्रमुख कमानों में से एक है।
- अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है।

पी. कुमारन ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला



- पी. कुमार ने 14 मई 2026 को लंदन में भारत के नामित उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।
- उन्होंने राजनयिक कोर के उप-मार्शल स्कॉट फर्सेडॉन-वुड को अपने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किए और औपचारिक रूप से इन्हें किंग चार्ल्स तृतीय को प्रस्तुत किया जाना था।
- वह वर्ष 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं और इससे पहले विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) के पद पर कार्य कर चुके हैं।
- उन्होंने पूर्व में वर्ष 2016 से 2020 तक कतर में भारत के राजदूत तथा वर्ष 2020 से 2023 तक सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी सेवा दी थी।

स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनीं भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैट-ए फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर



- स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना में प्रतिष्ठित कैट-ए क्वालिफाइड फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर (क्यूएफआई) योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- भारतीय वायुसेना ने उनकी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और उनके समर्पण तथा उत्कृष्टता के प्रयासों की सराहना की।
- यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं द्वारा बाधाएँ तोड़ने का एक और उदाहरण मानी गई।
- आईएफ ने कहा कि उनकी सफलता देशभर के भावी एविएटर्स को प्रेरित करेगी।

आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने यूआईडीएआई के सीईओ का कार्यभार संभाला



- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का कार्यभार संभाला।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार का प्रबंधन करता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम माना जाता है।
- सौरभ विजय भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1998 बैच के अधिकारी हैं।
- यूआईडीएआई में शामिल होने से पहले वे महाराष्ट्र वित्त विभाग में प्रधान सचिव (व्यय) के पद पर कार्यरत थे।

स्थैतिक बिंदु

- यूआईडीएआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के अंतर्गत कार्य करता है।
- यूआईडीएआई का उद्देश्य भारतीय निवासियों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण मंच प्रदान करना है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए



- भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
- इस समझौते के तहत भारत के 100% निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी, जिससे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण तथा इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
- समझौते में 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग मजबूत होगा।
- इसमें एमएसएमई, स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों और सहायता प्रणालियों तक बेहतर पहुँच मिलेगी।
- भारत ने डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ टैरिफ श्रेणियों को समझौते से बाहर रखा है।
- एफटीए बाजार पहुँच बढ़ाने, व्यापार बाधाएँ कम करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में सहायक होगा।
- समझौते में छात्र गतिशीलता से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके तहत स्टेम स्नातकों और कुशल पेशेवरों के लिए अध्ययन उपरांत कार्य वीजा की सुविधा दी जाएगी।
- न्यूजीलैंड ने पहली बार स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं, जिसमें आयुष भी शामिल है, के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराए हैं।
- यह समझौता कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है तथा भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक बना हुआ है।

स्थैतिक बिंदु

- एफटीए – मुक्त व्यापार समझौता
- न्यूजीलैंड की राजधानी – वेलिंगटन

डाक विभाग और डीटीडीसी ने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करने के लिए समझौता किया



- डाक विभाग और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने भारतभर में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के तहत डीटीडीसी को देशभर में डाक विभाग के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त होगी।
- साझेदारी का मुख्य फोकस दूरराज क्षेत्रों में केश ऑन डिलीवरी (सीओडी) सेवाओं सहित पार्सल डिलीवरी संचालन को बेहतर बनाना है।
- एमओयू का उद्देश्य संयुक्त लॉजिस्टिक्स संचालन, क्षमता साझाकरण और विपणन रणनीतियों के समन्वय को बढ़ावा देना है।
- दोनों संगठनों ने प्रगति की समीक्षा और लॉजिस्टिक्स सहयोग के विस्तार के लिए त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया।

भारत-वियतनाम ने परमाणु सहयोग मजबूत किया, कोबाल्ट-60 आपूर्ति पर चर्चा हुई

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो लाम के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यापक वार्ता हुई।



- दोनों देशों ने अपने संबंधों को “एन्हांसड कॉम्प्रिहेन्सिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” के स्तर तक उन्नत किया।
- भारत और वियतनाम ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जबकि वियतनाम ने भारत को अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया।
- वियतनाम ने कोबाल्ट-60 की आपूर्ति के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने इसकी निरंतर आपूर्ति की संभावनाओं पर सहमति जताई।
- दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु लचीलापन और आपदा-रोधी प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।
- वियतनाम ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में शामिल होने में रुचि दिखाई, जिसका भारत ने स्वागत किया।
- दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों को भी रेखांकित किया।
- भारत ने वर्ष 2030 तक वियतनाम के साथ 25 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में व्यापार 16 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है।
- सहयोग को महत्वपूर्ण खनिज, रेयर अर्थ, सप्लाई चेन, स्मार्ट कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

स्थैतिक बिंदु

- वियतनाम, भारत की एक ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत महत्वपूर्ण साझेदार है।
- Cकोबाल्ट-60 का उपयोग चिकित्सा उपचार, स्टेरिलाइजेशन और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है।

भारत और यूएई ने एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए



- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 15 मई 2026 को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और भारत को एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ये समझौते भारतीय प्रधानमंत्री की अबू धाबी यात्रा और यूएई नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान किए गए।
- यूएई भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बना रहा, जो भारत की कुल एलपीजी आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करता है।
- यूएई भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत भी रहा, जिसकी भारत के कुल कच्चे तेल आयात में लगभग 11% हिस्सेदारी रही।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ऊर्जा सुरक्षा के लिए बनाए गए आपातकालीन कच्चे तेल भंडार होते हैं।
- अन्य समझौतों में रक्षा साझेदारी, गुजरात में जहाज मरम्मत क्लस्टर और भारतीय अवसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्रों में यूएई के निवेश भी शामिल रहे।

भारत और नीदरलैंड्स ने कल्पसर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया



- भारत और नीदरलैंड्स ने गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए जल प्रबंधन, तटीय इंजीनियरिंग, जलवायु सहनशीलता और सतत अवसंरचना विकास में विशेषज्ञता बढ़ाने हेतु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह साझेदारी खंभात की खाड़ी में प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए डच विशेषज्ञों और गुजरात प्रशासन के बीच तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है।
- कल्पसर परियोजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी पर बांध बनाकर अरब सागर में बहने वाले अतिरिक्त नदी जल को संग्रहित करने हेतु विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार करना है।
- इस परियोजना से गुजरात में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों और डेल्टा इंजीनियरिंग के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध नीदरलैंड्स समुद्री जल विज्ञान, तलछट नियंत्रण और तटीय सुरक्षा से संबंधित तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराएगा।

स्थैतिक जीके

- खंभात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है।
- नीदरलैंड्स को निम्न भू-भाग होने के कारण “लो कंट्रीज” कहा जाता है।
- एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की संवैधानिक राजधानी है, जबकि हेग में सरकार और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित हैं।

महाराष्ट्र ने 25,400 मेगावाट परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया



- महाराष्ट्र ने 19 मई 2026 को कुल 25,400 मेगावाट क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चार कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- इन समझौतों की घोषणा मुंबई स्थित महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय मंत्रालय में की गई।
- इन परियोजनाओं में एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
- प्रस्तावित परमाणु परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित निवेश लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये बताया गया।
- अडानी पावर लिमिटेड ने रत्नागिरी जिले के बारसू में 6,000 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना बनाई, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रत्नागिरी के पूर्णागढ़ में 7,200 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर्स या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
- एनटीपीसी लिमिटेड ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 7,200 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना की योजना बनाई।
- ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5,000 मेगावाट परियोजना का प्रस्ताव दिया।
- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) को मॉड्यूलर निर्माण और कम इकाई क्षमता वाले कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टरों के रूप में बताया गया।
- भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में यूरेनियम आधारित परमाणु विखंडन रिएक्टरों के माध्यम से किया जाता है।

भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली



- भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और 14 मई 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” थीम पर आधारित रही।
- भारत ने चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और बहुपक्षवाद, सतत विकास तथा आर्थिक लचीलापन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।
- भारत ने वैश्विक दक्षिण के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारों पर जोर दिया।
- ब्रिक्स देशों की संयुक्त हिस्सेदारी वैश्विक जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक जीडीपी में 32% से अधिक रही।
- समूह ने वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाओं और वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के मुद्दों पर भी चर्चा की।
- ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका गठन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वर्ष 2026 में इसके विस्तारित सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया शामिल रहे।

भारत की अध्यक्षता में मुंबई में किम्बर्ले प्रोसेस अंतरिम सत्र 2026 संपन्न हुआ



- भारत की अध्यक्षता में किम्बर्ले प्रोसेस (केपी) अंतरिम सत्र 2026 मुंबई में वैश्विक प्राकृतिक हीरा क्षेत्र के भविष्य पर चार दिनों तक चली चर्चाओं के बाद संपन्न हुआ।
- भारत की वर्ष 2026 की अध्यक्षता का विषय “3Cs” — क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस — पर आधारित था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक हीरा मूल्य श्रृंखला में विश्वास को मजबूत करना है।
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिम्मेदार स्रोत व्यवस्था, पारदर्शिता और सतत हीरा व्यापार प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- इस बैठक में केपी प्रतिभागियों, पर्यवेक्षकों, उद्योग संगठनों, नागरिक समाज संस्थाओं और वर्ल्ड डायमंड काउंसिल ने शासन व्यवस्था, अनुपालन और निगरानी प्रणालियों पर चर्चा की।
- चर्चाओं का मुख्य फोकस कारीगर आधारित हीरा उत्पादन, सांख्यिकीय प्रणालियों, परिचालन सुधारों और नैतिक रूप से प्राप्त प्राकृतिक हीरों पर उपभोक्ता विश्वास से जुड़े मुद्दों पर रहा।
- केपी चेयर 2026 सुचिंद्र मिश्रा ने कहा कि बदलते वैश्विक हीरा बाजार में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किम्बर्ले प्रोसेस अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- विश्व के प्रमुख हीरा कटाई और पॉलिशिंग केंद्र के रूप में भारत ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के हीरों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के समर्थन को दोहराया।
- मुंबई बैठक की सिफारिशों पर आगे की चर्चा वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले केपी पूर्ण सत्र में जारी रहेगी।

अतिरिक्त जानकारी

- किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) की शुरुआत वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55/56 (2000) के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य “ब्लड डायमंड्स” को वैध व्यापार में प्रवेश करने से रोकना है।
- वर्तमान में केपी में 60 प्रतिभागी हैं, जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यूरोपीय संघ एकल समूह के रूप में भाग लेता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई 2026 को अपनी पाँच देशों की यूरोप यात्रा के दौरान ओस्लो में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।



- इस शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के नेताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, आर्कटिक अनुसंधान और व्यापार में भारत-नॉर्डिक सहयोग को मजबूत करना था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-नॉर्वे संबंधों को “ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” का दर्जा दिया।

- भारत और नॉर्वे ने अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और ग्लोबल साउथ के लिए त्रिपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- नॉर्वे ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट” से सम्मानित किया।
- यह वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में पहली नॉर्वे यात्रा थी।

स्थैतिक जीके

- नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं।
- इससे पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम (2018) और कोपेनहेगन (2022) में आयोजित हुए थे।

भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता: सिपरी



- भारत वर्ष 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा व्यय के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता रहा।
- रक्षा खर्च में वर्ष-दर-वर्ष 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक सैन्य व्यय का लगभग 3.2% है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी ने भारत से अधिक रक्षा खर्च किया।
- **रक्षा व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारण:**
 - ◆ सैन्य आधुनिकीकरण, जिसमें विमान, ड्रोन और मिसाइल प्रणालियाँ शामिल हैं
 - ◆ सीमा सुरक्षा और पर्वतीय युद्ध तैयारी को मजबूत करना
 - ◆ परिचालन एवं आपातकालीन खरीद, जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी आवश्यकताएँ
- क्षेत्रीय तुलना में पाकिस्तान ने 11.9 अरब डॉलर का रक्षा खर्च किया और वह वैश्विक स्तर पर 31वें स्थान पर रहा, जबकि चीन 336 अरब डॉलर के खर्च के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर रिकॉर्ड 2.89 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो लगातार 11वें वर्ष वृद्धि को दर्शाता है।
- यह भारत के रक्षा क्षमता विस्तार और रणनीतिक तैयारियों पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

स्थैतिक बिंदु

- सिपरी – स्वीडन स्थित थिंक टैंक
- भारत की वैश्विक रैंक – 5वीं

नीति आयोग ने डीपीआई@2047 रोडमैप लॉन्च किया



- नीति आयोग ने 27 अप्रैल 2026 को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीपीआई@2047 रोडमैप लॉन्च किया।
- इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के माध्यम से समावेशी, गैर-रेखीय और उत्पादकता आधारित विकास को बढ़ावा देना है।
- इस रोडमैप का शुभारंभ सुमन बेरी और अजय कुमार सूद द्वारा किया गया।
- इसे एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉइट के सहयोग से तैयार किया गया है।
- **रोडमैप को दो चरणों में विभाजित किया गया है:**
 - ◆ डीपीआई 2.0 (2025–2035) – आजीविका सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर फोकस
 - ◆ डीपीआई 3.0 (2035–2047) – व्यापक समृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य
- इस पहल का मुख्य फोकस एमएसएमई, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर है।
- इसके प्रमुख सक्षम तत्वों में ऋण उपलब्धता, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, एआई एकीकरण और प्रभावी लाभ वितरण प्रणाली शामिल हैं।
- कार्यान्वयन के प्रमुख स्तंभों में जिला स्तर की मांग, तकनीकी उद्यमिता, एआई अपनाना और बेहतर डेटा उपयोग शामिल हैं।
- यह पहल डीपीआई को पहचान और भुगतान प्रणाली से आगे बढ़ाकर आजीविका, बाजार पहुँच और आर्थिक परिवर्तन तक विस्तारित करती है।
- यह वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को समर्थन प्रदान करती है।

स्थैतिक बिंदु

- डीपीआई – डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
- नीति आयोग – स्थापना वर्ष 2015

स्विस री रिपोर्ट: भारत में बीमा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ा



- स्विस री रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रीमियम मात्रा के आधार पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार बन गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में बीमा पैठ 3.7% रही, जिसमें जीवन बीमा की हिस्सेदारी 2.7% और गैर-जीवन बीमा की हिस्सेदारी 1% रही।
- घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में बीमा और पेंशन फंड की हिस्सेदारी बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 29.6% हो गई।
- वर्ष 2025 के “सबका बीमा, सबकी रक्षा अधिनियम” के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।
- 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी छूट प्रदान की गई।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में फरवरी 2026 तक 26.88 करोड़ नामांकन और 10.45 लाख से अधिक दावों का निपटान किया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 57.11 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए, जिसके तहत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया गया।
- आयुष्मान भारत पीएम-जय योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया।
- सरकार ने वर्ष 2024 में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को शामिल किया।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 93.98 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए और 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया।
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पूरे भारत में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए “2047 तक सभी के लिए बीमा” का विजन अपनाया है।

नीति आयोग ने प्रभावी शहरी शासन पर रिपोर्ट जारी की

- नीति आयोग ने 25 अप्रैल 2026 को “मूविंग टुवार्ड्स एफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट – ए फ्रेमवर्क फॉर मिलियन-प्लस सिटीज” शीर्षक रिपोर्ट जारी की।
- केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस रिपोर्ट का विमोचन किया।



- यह रिपोर्ट विकसित भारत 2047 के विजन को समर्थन देने के लिए भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।
- रिपोर्ट में कमजोर नेतृत्व, सीमित वित्तीय स्वायत्तता और बिखरी हुई संस्थागत संरचनाओं जैसी प्रमुख शहरी चुनौतियों को उजागर किया गया है।
- नीति आयोग ने बेहतर जवाबदेही और प्रशासन के लिए निश्चित कार्यकाल वाले प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौरों की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
- रिपोर्ट में जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं को शहर सरकारों के नियंत्रण में लाने का सुझाव दिया गया है।
- इसमें बेहतर राजस्व सृजन और नगरपालिका बॉन्ड्स के माध्यम से नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की भी सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य नगरपालिका अधिनियमों में सुधार और मॉडल म्युनिसिपल लॉ को अद्यतन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

तमिलनाडु 2025 में देश का सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य बना: सीएमएफआरआई डेटा



- तमिलनाडु ने वर्ष 2025 में गुजरात को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य बनने का स्थान हासिल किया।
- प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गुजरात में मछली उत्पादन में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे वह दूसरे स्थान पर खिसक गया।
- इसके प्रमुख कारण खराब मौसम, 60-75 दिनों तक विस्तारित मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और चक्रवाती व्यवधान, जैसे चक्रवात शक्ति, रहे।
- ऑपरेशन सिंदूर के तहत मई के मध्य में लगाए गए मछली पकड़ने संबंधी प्रतिबंधों से भी मछली पकड़ने की गतिविधियाँ प्रभावित हुईं।

- भारत का कुल समुद्री मछली उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष लगभग 3% बढ़कर 3.57 मिलियन टन हो गया।
- केरल 0.62 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर बना रहा।
- कर्नाटक में उत्पादन में 43% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में 16% की बढ़ोतरी हुई।
- यह आँकड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा जारी किए गए।
- यह रिपोर्ट मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन पर जलवायु और नियामकीय कारकों के प्रभाव को दर्शाती है।

स्थैतिक बिंदु

- आईसीएआर – भारत की प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्था
- सीएमएफआरआई मुख्यालय – कोच्चि

भारत 2024 में 137 अरब डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त कर दुनिया में शीर्ष पर: संयुक्त राष्ट्र



- भारत ने वर्ष 2024 में 137 अरब डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त किया, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बन गया।
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत 100 अरब डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है।
- अन्य प्रमुख प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में मेक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस शामिल हैं।
- भारत वर्ष 2010 से लगातार सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना हुआ है और प्रेषण राशि लगभग 53 अरब डॉलर (2010) से बढ़कर 137 अरब डॉलर (2024) तक पहुँच गई है।
- दक्षिण एशिया में प्रेषण में सबसे अधिक 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रमुख भूमिका रही।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 100 अरब डॉलर से अधिक राशि के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण भेजने वाला देश बना रहा, जिसके बाद सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का स्थान रहा।

स्थैतिक बिंदु

- प्रेषण वह धनराशि होती है, जिसे प्रवासी अपने परिवार और घरेलू अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए अपने देश भेजते हैं।

एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान



- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.5% आंकी गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
- वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में ऋण वृद्धि मजबूत रहने की संभावना जताई गई है।
- मजबूत घरेलू खपत आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने की संभावना है।
- रबी फसल के बेहतर उत्पादन से निकट अवधि में खाद्य आपूर्ति की स्थिति मजबूत हुई है।
- कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा संभावित एल नीनो परिस्थितियाँ महंगाई जोखिम बढ़ा सकती हैं।
- रिपोर्ट में रुपये के अवमूल्यन और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों से उत्पन्न भुगतान संतुलन दबाव को संभालने के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज की आवश्यकता बताई गई।
- इसमें निवेशकों के अनुकूल कर व्यवस्था के साथ भारतीय प्रवासी बॉन्ड के संतुलित उपयोग की सिफारिश की गई।
- रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में एआई ने जीडीपी वृद्धि में प्रतिवर्ष 0.1% से 0.5% तक योगदान दिया।
- रिपोर्ट ने भारत को उपयुक्त नीतियों के माध्यम से एआई आधारित उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2025 रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की गई



- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LEADS 2025 रिपोर्ट जारी की।
- LEADS (लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए वार्षिक बेंचमार्किंग ढाँचे के रूप में कार्य करता है।

- यह रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई।
- LEADS 2025 इसका सातवाँ संस्करण था, जिसमें अवसंरचना, सेवाओं, नीतिगत ढाँचे और परिचालन वातावरण के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रणाली का आकलन किया गया।
- वर्ष 2025 संस्करण में एक्सेम्प्लर्स, हाई परफॉर्मर्स, एक्सेलेरेटर्स और ग्रोथ सीकर्स की चार-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली लागू की गई।
- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली को उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के लिए एक्सेम्प्लर्स श्रेणी में रखा गया।
- गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना को लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में हाई परफॉर्मर्स के रूप में स्थान दिया गया।
- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और कर्नाटक को सुधार की गति दिखाने वाले एक्सेलेरेटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- पश्चिम बंगाल, राजस्थान और सिक्किम को प्रारंभिक स्तर वाले ग्रोथ सीकर्स वर्ग में रखा गया।
- यह रिपोर्ट भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप तैयार की गई।

शिवा नरवाल ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में स्वर्ण जीता



- शिवा नरवाल ने काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- उन्होंने फाइनल में 241.8 अंक हासिल किए और क्वालिफिकेशन राउंड में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- सोडिकजोन अब्दुल्लाएव ने 240.0 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि चिराग शर्मा ने 218.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
- पनाह भुगरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 250.6 अंक के साथ रजत पदक जीता।
- भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- इस टूर्नामेंट में 25 देशों के 284 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत ने सबसे बड़ा 71 सदस्यीय दल भेजा है।

सबास्टियन सावे ने 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर इतिहास रचा



- केन्या के एथलीट सबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 को 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर इतिहास रच दिया।

- वह आधिकारिक रूप से मैराथन को 2 घंटे से कम समय में पूरा करने वाले पहले एथलीट बने और नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।
- सावे ने केल्विन किप्टम के 2:00:35 के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा।
- लंदन मैराथन 2026 अब तक के सबसे तेज मैराथन आयोजनों में शामिल हो गया, जिसमें कई एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया।
- योमिफ केजेल्चा सावे से केवल 11 सेकंड पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जैकब किप्लिमो ने भी पिछले विश्व रिकॉर्ड समय से बेहतर प्रदर्शन किया।
- महिला वर्ग में टिस्ट असेफा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा।

पी. वी. सिंधु बीडब्ल्यूएफ परिषद की मतदान सदस्य बनीं



- ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की एथलीट्स आयोग की अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीडब्ल्यूएफ परिषद की मतदान सदस्य बन गईं।
- उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि एक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को वैश्विक बैडमिंटन प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी मिली है।
- पी. वी. सिंधु ने वर्ष 2025 के अंत में औपचारिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से बीडब्ल्यूएफ परिषद में शामिल हुईं।
- उन्होंने हॉर्सेन्स में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वार्षिक आम बैठक के दौरान परिषद सदस्य के रूप में पहली बार भाग लिया।
- मतदान सदस्य के रूप में सिंधु को वैश्विक बैडमिंटन के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ियों के हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व भी करेंगी।

- सिंधु की भूमिका में नीति निर्माण, खिलाड़ी कल्याण और बैडमिंटन विश्व महासंघ की विकास रणनीतियों में योगदान देना शामिल है।

भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चार स्वर्ण पदक जीते



- सामोआ के एपिया में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन किया।
- भारत ने युवा, जूनियर और सीनियर वर्गों में कुल चार स्वर्ण पदक जीतकर भारोत्तोलन में अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया।
- सुनील सिंह ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कुल 271 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता।
- ऐसांगफा गोगोई ने महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में कुल 185 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया।
- अभिनोब गोगोई ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में कुल 284 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
- चारु पेसी ने यूनिवर्सल कप सीनियर स्पर्धा में कुल 289 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय खिलाड़ियों में सबसे अधिक रहा।

ऋतिका श्री बनीं भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर



- तमिलनाडु की ऋतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनकर इतिहास रच दिया।
- यह उपलब्धि तमिलनाडु क्रिकेट संघ द्वारा अंपायर परीक्षा प्रक्रिया में 'अन्य' श्रेणी शुरू करने के निर्णय के बाद संभव हुई।
- यह पहल भारतीय क्रिकेट प्रशासन में लैंगिक समावेशन और समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
- ऋतिका श्री ने वर्ष 2021 में अपने अंपायरिंग करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने सलेम तथा कोयंबटूर क्रिकेट सर्किट में मैचों में अंपायरिंग की।
- सामाजिक भेदभाव और क्रिकेट मैदानों तक पहुँच में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ अपनी यात्रा जारी रखी।
- भारत ने वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आधिकारिक रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी।

ताशकंद में एशियाई अंडर-15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 पदक पक्का किया



- उज्बेकिस्तान के तашकंद में आयोजित एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों ने 27 पदक सुनिश्चित किए।
- भारतीय मुक्केबाजों ने आक्रामक रणनीति और शानदार तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

मार्टा कोस्त्युक ने मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब जीता



- मार्टा कोस्त्युक ने मैड्रिड ओपन 2026 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। 23 वर्षीय यूक्रेनी खिलाड़ी ने महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर-8 मीरा एंड्रीवा को 6-3, 7-5 से हराया।

- कोस्त्युक सोमवार को जारी होने वाली डब्ल्यूटीए रैंकिंग में विश्व नंबर-23 से अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 15वीं रैंक पर पहुँचने वाली हैं।
- यह उनके करियर का तीसरा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब है और अब वह 24 मई से पेरिस में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन की प्रमुख दावेदारों में शामिल हो गई हैं।

मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा



- मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में आयोजित पहले इंडियन इंडोर ओपन संयुक्त स्पर्धा एवं पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के उद्घाटन दिवस पर 5.41 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वॉल्ट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता।
- 21 वर्षीय कुलदीप ने अपने पहले प्रयास में 5.41 मीटर की ऊँचाई पार करते हुए देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। साथ ही उन्होंने मार्च में तमिलनाडु के रीगन जी द्वारा बनाए गए 5.30 मीटर के इंडोर रिकॉर्ड में भी सुधार किया।

सात वर्षीय ईशांक सिंह पाल्क जलडमरूमध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने



- झारखंड के सात वर्षीय बालक ने पाल्क जलडमरूमध्य पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया। उसने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी अपनी आयु वर्ग में रिकॉर्ड समय में पूरी की।
- रांची के कक्षा 3 के छात्र ईशांक सिंह ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक की तैराकी 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। इस उपलब्धि को यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने आधिकारिक मान्यता दी।

भारतीय मूल के गोल्फर आरोन राय ने 2026 पीजीए चैंपियनशिप जीती



- भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर आरोन राय ने अमेरिका के पेनसिल्वेनिया स्थित एरोनिमिक गोल्फ क्लब में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर अपना पहला मेजर गोल्फ खिताब हासिल किया।
- आरोन राय वर्ष 1919 में जिम बार्न्स के बाद पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले एक सदी से अधिक समय में पहले अंग्रेज गोल्फर बने।
- उन्होंने सात-अंडर-पार स्कोर के साथ प्रतियोगिता समाप्त की और अंतिम तालिका में जॉन रहम तथा एलेक्स स्मॉले को तीन स्ट्रोक से हराया।
- आरोन राय अपने शांत स्वभाव, अनुशासित खेल और खेल के दौरान दोनों हाथों में दस्ताने पहनने की अनोखी आदत के लिए प्रसिद्ध हैं।
- राय ने अंतिम राउंड में एक ईगल और कई बर्डी लगाकर दबावपूर्ण परिस्थितियों में शानदार वापसी की।

स्थैतिक जीके

- पीजीए चैंपियनशिप गोल्फ की चार प्रमुख चैंपियनशिप में से एक है।
- इसका आयोजन प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा किया जाता है।
- टाइगर वुड्स यह टूर्नामेंट चार बार जीत चुके हैं।
- गोल्फ वर्ष 2016 में 112 साल बाद ओलंपिक खेलों में वापस शामिल हुआ था।

यानिक सिनर ने इटालियन ओपन 2026 जीतकर इतिहास रचा



- विश्व नंबर-1 यानिक सिनर ने रोम में खेले गए पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर 2026 इटालियन ओपन का खिताब जीता।

- इस जीत के साथ सिनर 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने। इससे पहले वर्ष 1976 में एड्रियानो पनाटा ने यह उपलब्धि हासिल की थी।
- इस जीत के साथ सिनर ने प्रतिष्ठित “कैरियर गोल्डन मास्टर्स” भी पूरा कर लिया, यानी उन्होंने अब सभी नौ एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीत लिए हैं। वह नोवाक जोकोविच के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने।
- सिर्फ 24 वर्ष की आयु में सिनर “कैरियर गोल्डन मास्टर्स” पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए।
- यह टूर्नामेंट इटली के रोम स्थित फोरो इटालिको में आयोजित किया गया, जिसे फ्रेंच ओपन से पहले प्रमुख क्ले-कोर्ट प्रतियोगिताओं में गिना जाता है।
- सिनर ने अपनी शानदार एटीपी मास्टर्स जीत श्रृंखला को आगे बढ़ाया और फ्रेंच ओपन में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में प्रवेश किया।
- इटली की जोड़ी सिमोने बोलेली और आंद्रेया वावासोरी ने पुरुष युगल खिताब भी जीता।

स्थैतिक जीके

- इटालियन ओपन रोम में क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है।
- फ्रेंच ओपन पेरिस के रोलांग गैरो में आयोजित किया जाता है।
- एटीपी का पूर्ण रूप – एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स।

भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 10 पदकों के साथ अभियान समाप्त किया

- भारत ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का समापन 10 पदकों के साथ किया, जिनमें एक रजत और नौ कांस्य पदक शामिल रहे। यह चीन के जियांगशान में आयोजित पिछले संस्करण की तुलना में बड़ा सुधार रहा, जहाँ भारत कोई पदक नहीं जीत पाया था।
- यह चैंपियनशिप 11 से 17 मई 2026 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हुई, जिसमें एशिया के 28 देशों ने भाग लिया।



- ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा स्नैच वर्ग में रजत पदक और कुल भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
- कोमल कोहर ने ओलंपिक पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू की जगह लेते हुए महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला।
- अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किग्रा वर्ग में दो कांस्य पदक जीतकर 15 वर्षों में एक ही एशियाई चैंपियनशिप संस्करण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष भारोत्तोलक बने।
- संजना ने महिलाओं के 77 किग्रा वर्ग में कुल 220 किग्रा भार उठाकर तीन कांस्य पदक अपने नाम किए।
- कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किग्रा+ वर्ग में 386 किग्रा के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कुल भार के साथ पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया।

स्थैतिक जीके

- एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन बेटलिफ्टिंग फेडरेशन (एडब्ल्यूएफ) द्वारा किया जाता है।
- भारत ने इससे पहले वर्ष 1982 में नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।
- स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार वर्ग के लिए अलग-अलग पदक प्रदान किए जाते हैं।



आर्थर लॉ को विश्व आर्थिक मंच ने 2026 का यंग ग्लोबल लीडर चुना



- आर्थर लॉ स्टोरफ्रेडली एशिया के सह-संस्थापक हैं, जो प्रौद्योगिकी आधारित सेल्फ-स्टोरेज प्लेटफॉर्म है।
- उन्हें शहरी स्थान प्रबंधन और सतत विकास में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है।
- उनकी कंपनी घनी आबादी वाले शहरों में 40,000 से अधिक परिवारों और व्यवसायों को सेवाएँ प्रदान करती है।
- कंपनी को ब्लैकस्टोन और पार्टनर्स ग्रुप जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है।
- यंग ग्लोबल लीडर्स 2026 के तहत 55 देशों के 118 नेताओं का चयन किया गया।
- आर्थर लॉ पहले गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी जैसी कंपनियों में कार्य कर चुके हैं।
- वे द केएलई फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हुए हैं।

उपेंद्र द्विवेदी अमेरिकी आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए



- सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पेनसिल्वेनिया स्थित प्रतिष्ठित अमेरिकी आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- वह पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह और बिक्रम सिंह के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बने।
- यह सम्मान समारोह कार्लिसल बैरक्स में आयोजित किया गया, जो अमेरिकी आर्मी वॉर कॉलेज का मुख्यालय है।
- जनरल द्विवेदी को उनकी उत्कृष्ट सैन्य सेवा, रणनीतिक नेतृत्व और वैश्विक रक्षा सहयोग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- अमेरिका यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर चर्चा की।

सुर ज्योत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से दिग्गज कलाकार सम्मानित



- सुर ज्योत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया।
- प्रसिद्ध गायिका सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को भारत की संगीत विरासत के संरक्षण में आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- इन पुरस्कारों के माध्यम से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनके दशकों लंबे समर्पण को मान्यता दी गई।
- सुर ज्योत्स्ना पुरस्कार ज्योत्स्ना दरडा की स्मृति में भारतीय संगीत परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से शुरू किए गए थे।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में युवा और उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करना भी है।
- यह समारोह डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में कई विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की



- सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की, जिसके तहत देशभर से 42 पंचायतों का चयन किया गया।
- पुरस्कार समारोह 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- कर्नाटक ने 6 पंचायतों के साथ सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 5-5 पुरस्कार मिले।
- पुरस्कार दो श्रेणियों — दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार — के तहत दिए जाते हैं।
- दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल पर्याप्तता, महिला अनुकूल शासन और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं।
- इस श्रेणी में 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कुल 34 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।
- नानाजी देशमुख श्रेणी के तहत 8 पंचायतों का चयन किया गया, जिनमें जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
- विजेता पंचायतों को 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

स्थैतिक बिंदु

- पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के लिए नोडल मंत्रालय है।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ।



- ये पुरस्कार केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों के अंतर्गत कार्यरत पंजीकृत नर्सों, दाइयों, सहायक नर्स मिडवाइफ और लेडी हेल्थ विजिटर्स को प्रदान किए जाते हैं।
- प्रत्येक पुरस्कार में स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान के सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपये की नकद राशि और एक पदक प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह अवसर नर्सिंग पेशेवरों की समर्पण भावना और करुणा को सम्मानित करने का प्रतीक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्यनिष्ठा और रोगी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।
- समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव भी उपस्थित रहे।
- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में समाज के प्रति नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी।

मेजर अभिलाषा बराक को जेंडर एडवोकेसी के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सम्मान मिला



- भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में जेंडर-समावेशी शांति अभियानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2025 के लिए चुना गया।
- वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल इन लेबनान (यूएनआईएफिल) के तहत भारतीय बटालियन में फीमेल एंजेजमेंट टीम (एफईटी) की कमांडर के रूप में कार्यरत हैं।

- मेजर बराक को महिलाओं और किशोरियों के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सैनिकों को जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने के लिए सम्मानित किया गया।
- वह भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भी जानी जाती हैं, जिसने भारत की रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित की।
- यह पुरस्कार 29 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदान किया जाएगा।
- मेजर अभिलाषा बराक इस सम्मान को प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बर्ती। इससे पहले मेजर सुमन गावनी और मेजर राधिका सेन को यह सम्मान मिल चुका है। यह वैश्विक शांति अभियानों और महिला-नेतृत्व वाली सैन्य पहलों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

स्थैतिक जीके तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना – 24 अक्टूबर 1945
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय – न्यूयॉर्क सिटी
- यूएनआईफिल की स्थापना – वर्ष 1978, दक्षिणी लेबनान में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए
- भारत विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मई 2026 को इटली के रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) मुख्यालय में एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया।



- यह पदक एफएओ के पूर्ण सत्र हॉल में क्यू डोंग्यू द्वारा प्रदान किया गया।
- एग्रीकोला मेडल को कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए एफएओ के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।
- एफएओ ने भारत की किसान वित्तीय समावेशन योजनाओं, 110 मिलियन से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता और लगभग 800 मिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की सराहना की।
- एफएओ ने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान मोटा अनाज को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को भी मान्यता दी।
- रोम यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और सर्जियो मातारेला से मुलाकात की।
- यह यात्रा लगभग 30 वर्षों में किसी भारतीय शासनाध्यक्ष की एफएओ मुख्यालय की पहली यात्रा मानी गई।

बिहार में आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत पहली संरचित दलहन खरीद शुरू



- सरकार ने पीएम-आशा योजना के तहत खरीद प्रक्रिया का विस्तार किया।
- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बिहार ने आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत अपनी पहली संरचित दलहन खरीद पहल शुरू की।
- एनसीसीएफ ने बिहार में पहली बार संगठित मसूर खरीद प्रक्रिया की शुरुआत की।
- बिहार में 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 100.4 मीट्रिक टन खरीद की गई और 59 किसानों को जोड़ा गया।
- छत्तीसगढ़ में ई-समयुक्ति पोर्टल और जागरूकता अभियानों के माध्यम से खरीद प्रणाली को मजबूत किया गया।
- खरीद आँकड़ों के अनुसार, एनसीसीएफ ने 9,032 मीट्रिक टन चना और 7.98 मीट्रिक टन मसूर की खरीद की, जबकि नेफेड ने 3,850 मीट्रिक टन चना और 109 मीट्रिक टन मसूर खरीदा।

स्थैतिक बिंदु

- पीएम-आशा योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी।
- नेफेड की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी।

1 जुलाई से पूरे भारत में लागू होगी VB-G RAM G योजना, मनरेगा की लेगी जगह

- केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत – गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी की।



- यह नया अधिनियम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा।
- नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।
- ई-केवाईसी सत्यापित मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे।
- मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य नए ढाँचे में बिना रुकावट जारी रहेंगे।
- लंबित ई-केवाईसी सत्यापन के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- मजदूरी का भुगतान सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से बैंक या डाकघर खातों में जारी रहेगा।
- भुगतान साप्ताहिक या 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा श्रमिकों को विलंब मुआवजा दिया जाएगा।
- केंद्र ने बजट 2026-27 में इस कार्यक्रम के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो किसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यों को संचालन संबंधी तैयारियों के लिए छह महीने तक का समय दिया जा सकता है।

स्थैतिक बिंदु

- मनरेगा की शुरुआत – वर्ष 2005
- भारत में ग्रामीण रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

घरेलू कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने हेतु 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।



- इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को समर्थन देना है।
- यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू की गई है।
- योजना का मुख्य फोकस एलएनजी, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल के आयात को कम करना है।
- सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकिंग अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष तक कर दिया है।
- नई परियोजनाओं के लिए संयंत्र और मशीनरी लागत का 20% तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत लगभग 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- नीति का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और स्वच्छ कोयला उपयोग को बढ़ावा देना है।
- नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो लक्ष्यों पर अपनी रिपोर्ट में कोयला गैसीकरण और CCUS को स्वच्छ कोयला उपयोग के महत्वपूर्ण अवसर बताया।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 189.79 करोड़ रुपये के मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की

- केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और लालदुहोमा ने मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की।

- इस मिशन के तहत मिजोरम में अदरक की खेती और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए 189.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।



- इस पहल का संचालन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा किया जा रहा है।
- मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ समन्वय किया गया है।
- नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीड) जैसी संस्थाएँ इस पहल को समर्थन दे रही हैं।
- मिशन का मुख्य फोकस प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।
- इस पहल का उद्देश्य मूल्य अंतर को कम करना और मिजोरम के जीआई-प्रमाणित फार्मा-ग्रेड अदरक को बढ़ावा देना है।
- चम्फाई जिले के अदरक किसानों ने बाजार तक बेहतर पहुँच और आजीविका सुधार के लिए इस मिशन का स्वागत किया।
- निजी क्षेत्र के साझेदारों ने मिजो अदरक को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
- मिजोरम सरकार ने मिशन के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नंदेंडला भास्कर राव का निधन



- आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नंदेंडला भास्कर राव का 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में आयु संबंधी बीमारी के कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- वर्ष 1984 के आंध्र प्रदेश राजनीतिक संकट में अपनी भूमिका के कारण वह दक्षिण भारत के सबसे विवादास्पद राजनीतिक नेताओं में से एक माने जाते थे।
- भास्कर राव ने 1984 के राजनीतिक घटनाक्रम से पहले एन. टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था।
- एनटीआर के इलाज के लिए अमेरिका दौर के दौरान भास्कर राव ने बहुमत समर्थन का दावा किया और 16 अगस्त 1984 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- उनकी नियुक्ति के बाद व्यापक राजनीतिक विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद एनटीआर ने लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए 'धर्म युद्धम' अभियान चलाया।
- केवल 31 दिनों के भीतर एन. टी. रामाराव को पुनः मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे भास्कर राव का कार्यकाल आंध्र प्रदेश के सबसे छोटे कार्यकालों में शामिल हो गया।
- वर्ष 1984 की इस राजनीतिक घटना ने संवैधानिक मर्यादा, राज्यपाल की भूमिका और भारत में संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी।
- वह वर्ष 1982 में तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और बाद में 1984 के संकट के बाद कांग्रेस में वापस शामिल हो गए।

दुनिया का पहला 24 घंटे का समाचार चैनल बनाने वाले टेड टर्नर का निधन

- विश्व के पहले 24 घंटे के समाचार चैनल की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध मीडिया उद्यमी टेड टर्नर का 6 मई 2026 को 87 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक निधन हो गया।



- टर्नर एंटरप्राइजेज के अनुसार, उनका निधन आधुनिक प्रसारण जगत के एक युग का अंत माना जा रहा है और उन्हें टेलीविजन समाचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा वैश्विक मीडिया विरासत स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
- अपने साहसी व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध टर्नर ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया, जिसने केबल टेलीविजन, खेल प्रसारण और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता को नई दिशा दी।
- टर्नर एंटरप्राइजेज ने बताया कि उनका निधन 6 मई 2026 को शांतिपूर्वक हुआ।
- उन्हें टेलीविजन समाचार की परिभाषा बदलने और वैश्विक मीडिया विरासत छोड़ने वाले व्यक्तित्व के रूप में व्यापक पहचान मिली।
- उनका निधन समकालीन प्रसारण जगत के एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।
- उन्होंने ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने केबल टेलीविजन, खेल प्रसारण और वैश्विक पत्रकारिता को बदल दिया।
- वह अपने साहसी व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षी सोच के लिए प्रसिद्ध थे।

पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन

- पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में लंबे समय से चली आ रही उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया।



- वर्ष 1935 में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे खंडूरी सक्रिय राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
- उन्होंने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया — पहली बार 2007 से 2009 तक और दूसरी बार 2011 से 2012 तक।

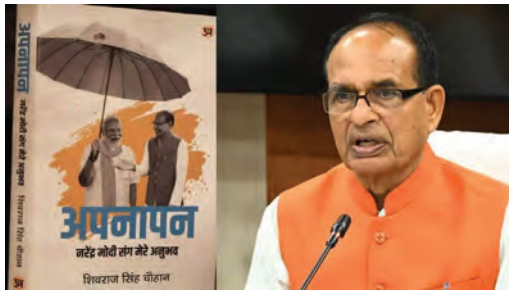
- खंडूरी पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार-रोधी कदमों और पर्वतीय राज्य में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध थे।
- केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।
- वह उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से कई बार सांसद भी चुने गए।

स्थैतिक जीके

- उत्तराखंड का गठन – 9 नवंबर 2000
- राजधानी – देहरादून (शीतकालीन) और गैरसैण (ग्रीष्मकालीन)
- उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री – नित्यानंद स्वामी
- राज्य पशु – अल्पाइन कस्तूरी मृग



केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 'अपनापन' पुस्तक का करेंगे विमोचन



- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों पर आधारित नई पुस्तक “अपनापन” के विमोचन की घोषणा की।
- इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन 26 मई 2026 को नई दिल्ली के पूसा स्थित एनएससी कॉम्प्लेक्स में पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की उपस्थिति में किया जाएगा।
- “अपनापन” में प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली, कार्य संस्कृति, अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है।
- शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनका संबंध नरेंद्र मोदी से वर्ष 1991 की एकता यात्रा के दौरान शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुरली मनोहर जोशी ने किया था।
- पुस्तक में शासन के अनुभव, नीतियों के क्रियान्वयन और राज्यों के बीच कैबिनेट स्तर के समन्वय पर भी चर्चा की गई है।

अन्य जानकारी

- शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं।
- वह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं।
- नरेंद्र मोदी मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
- वर्ष 1991 की एकता यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई थी।

उपराष्ट्रपति ने पी.एन. पनिककर पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया



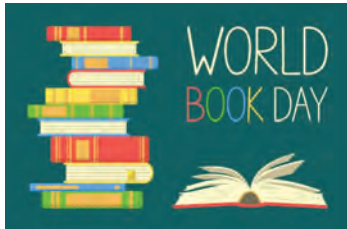
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पी.एन. पनिककर को समर्पित एक पुस्तक का विमोचन किया और युवाओं तथा समाज में भारत की पठन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पढ़ने को बौद्धिक विकास, जागरूक नागरिकता और डिजिटल युग में राष्ट्रीय विकास का शक्तिशाली माध्यम बताया।
- उपराष्ट्रपति ने केरल में साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलनों में पी.एन. पनिककर के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें भारत में जन-पठन अभियानों का अग्रदूत बताया।
- पी.एन. पनिककर को केरल में सार्वजनिक पुस्तकालयों और ग्रामीण समुदायों में साक्षरता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए “केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक” के रूप में याद किया जाता है।

स्थैतिक जीके तथ्य

- पी.एन. पनिककर की जयंती 19 जून को केरल में पठन दिवस के रूप में मनाई जाती है।
- जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं।
- भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं।



विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2026 मनाया गया



- विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्वभर में मनाया जाता है।
- यह दिवस पुस्तकों, लेखकों, पठन संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित है।
- इसका आयोजन यूनेस्को के मार्गदर्शन में किया जाता है।
- इस दिवस का मुख्य फोकस पठन-पाठन, प्रकाशन, शिक्षा और कॉपीराइट कानूनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- 23 अप्रैल का दिन महान साहित्यकारों की पुण्यतिथियों के कारण विशेष प्रतीकात्मक महत्व रखता है।
 - ♦ विलियम शेक्सपियर
 - ♦ मिगुएल डी सर्वैंटिस
- यह दिवस इस बात को रेखांकित करता है कि पुस्तकें विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने और पीढ़ियों तक ज्ञान संरक्षित रखने का माध्यम हैं।

स्थैतिक बिंदु

- यूनेस्को ने इस दिवस की घोषणा वर्ष 1995 में की थी।
- इसकी शुरुआत का संबंध 1920 के दशक के स्पेन से माना जाता है।

24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया



- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया।

- यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्मृति में मनाया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- वर्ष 2026 में 73वें संविधान संशोधन के 33 वर्ष पूर्ण हुए।
- पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम में भाग लिया।
- इस अवसर पर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई)-2.0 रिपोर्ट जारी की गई।
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देशभर में ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2026 मनाया गया



- अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2026 को विश्वभर में नृत्य को अभिव्यक्ति, संस्कृति और संचार के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया।
- इस दिवस को विश्व नृत्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है और यह सभी आयु वर्ग के लोगों को नृत्य एवं लय के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।
- इसका आयोजन यूनेस्को के सहयोग से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है।
- यह तिथि आधुनिक नृत्य रंगमंच के अग्रदूत जीन-जॉर्ज नोवेर की जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई है।
- वर्ष 2026 में इस दिवस का मुख्य फोकस रचनात्मकता, एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना रहा।
- यह दिवस नृत्य को केवल प्रदर्शन कला नहीं, बल्कि आत्म-अभिव्यक्ति, शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान के माध्यम के रूप में भी रेखांकित करता है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक भागीदारी बढ़ाना, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और शिक्षा प्रणाली में नृत्य को शामिल करना है।
- वर्ष 1982 में शुरू किए गए इस आयोजन ने नृत्य और कलाकारों को वैश्विक पहचान एवं व्यापक दृश्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्थैतिक बिंदु

- तिथि – 29 अप्रैल
- आईटीआई – स्थापना वर्ष 1948

अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 2026 मनाया गया



- अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसकी 15वीं वर्षगांठ मनाई गई।
- वर्ष 2026 के लिए शिकागो को वैश्विक मेजबान शहर चुना गया, जिसने जैज संगीत के विकास में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए विशेष पहचान प्राप्त की।
- इस दिवस की स्थापना वर्ष 2011 में हर्बी हैनकॉक की पहल पर यूनेस्को द्वारा की गई थी।
- यह दिवस जैज को एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा के रूप में मनाता है, जो एकता, शांति और अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देती है।
- इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाओं को कम करना तथा स्वतंत्रता, गरिमा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।
- इस अवसर पर वैश्विक संगीत कार्यक्रम, सामुदायिक जैम सत्र, मास्टरक्लास और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है।
- इसका वैश्विक संचालन यूनेस्को और हर्बी हैनकॉक इंस्टीट्यूट ऑफ जैज द्वारा किया जाता है, जिसमें कलाकारों, संस्थानों और सरकारों की भागीदारी रहती है।
- यह दिवस जैज प्रशंसा माह के समापन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज की विरासत और विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 मनाया गया



- अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिकों और उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है।
- इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जो उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और श्रमिक सम्मान जैसे मुद्दों को उजागर करता है।
- भारत में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहा जाता है।
- यह 80 से अधिक देशों में रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस ऐतिहासिक श्रमिक आंदोलनों को आधुनिक अर्थव्यवस्था और कार्यबल की चुनौतियों से जोड़ता है।
- इसकी उत्पत्ति हेयमार्केट घटना से मानी जाती है, जहाँ श्रमिकों ने 8 घंटे कार्यदिवस की मांग की थी।
- वर्ष 1889 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठनों ने 1 मई को श्रमिक दिवस घोषित किया।
- वर्ष 2026 की थीम थी — “एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना”
- यह थीम हीटवेव, अत्यधिक मौसम और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्यस्थल सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित है।
- यह दिवस सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

विश्व अस्थमा दिवस 2026, 5 मई को मनाया गया



- विश्व अस्थमा दिवस 2026, 5 मई को मनाया गया, जिसका उद्देश्य अस्थमा देखभाल और उपचार की उपलब्धता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
- विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है।
- ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा घोषित वर्ष 2026 की थीम थी — “अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति के लिए एंटी-इन्फ्लेमेटरी इनहेलर की उपलब्धता — अब भी एक जरूरी आवश्यकता”
- इसका मुख्य फोकस वायुमार्ग की सूजन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक इनहेलड कॉर्टिकोस्टेरोइड्स की उपलब्धता बढ़ाने पर रहा।
- विशेषज्ञों ने कहा कि केवल राहत देने वाले इनहेलर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए उचित दवाओं की आवश्यकता होती है।
- इनहेलड कॉर्टिकोस्टेरोइड्स सूजन कम करने, अस्थमा अटैक रोकने और अस्पताल में भर्ती होने व मृत्यु के जोखिम को घटाने में मदद करते हैं।

- डॉक्टरों ने लक्षणों से राहत और दीर्घकालिक नियंत्रण दोनों के लिए संयोजन (2-इन-1) इनहेलर के उपयोग की सलाह दी।
- विश्वभर में लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से प्रभावित हैं और हर वर्ष लगभग 4.5 लाख मौतें होती हैं, जिनमें अधिकांश रोकी जा सकती हैं।
- भारत जैसे देशों में प्रदूषण, कम जागरूकता और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अस्थमा का बोझ अधिक है।
- अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें वायुमार्ग में सूजन और संकुचन हो जाता है।

विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026, 7 मई को मनाया गया



- विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026, 7 मई को एथलेटिक्स को बढ़ावा देने और युवाओं की खेलों में भागीदारी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया गया।
- इस दिवस का आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है।
- वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस 2026 की आधिकारिक थीम अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा घोषित नहीं की गई है।
- वर्ष 2025 की थीम 'रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज' थी, जिसने टीमवर्क, एकता और भविष्य की पीढ़ियों तक एथलेटिक मूल्यों को पहुँचाने की भावना को रेखांकित किया था।
- यह पहल दौड़, कूद, श्रो और ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देती है।
- यह कार्यक्रम "एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड" वैश्विक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करना है।
- भारत में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस आयोजन को स्कूल, जिला और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देता है।
- यह दिवस युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और कोविड काल के बाद खेलों में भागीदारी को पुनर्जीवित करने में भी सहायक है।

स्थैतिक बिंदु

- वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना वर्ष 1912 में आईएएफ के रूप में हुई थी।
- मुख्यालय – मोनाको

पाकिस्तान ने 10 मई को "मार्का-ए-हक दिवस" घोषित किया



- पाकिस्तान ने वर्ष 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्मृति में 10 मई को वार्षिक "मार्का-ए-हक दिवस" घोषित किया।
- "मार्का-ए-हक" का अर्थ "सत्य की लड़ाई" बताया गया और यह 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक चले संघर्ष काल को संदर्भित करता है।
- इस दिवस की घोषणा इस्लामाबाद में की गई और इसे वर्ष 2025 के सैन्य टकराव की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया गया।
- पाकिस्तान ने कहा कि यह दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा, लेकिन इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा।
- वर्ष 2025 का संघर्ष पहलगांम घटना के बाद शुरू हुआ था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया।
- पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई को "ऑपरेशन बुनयान-उन-मरसूस" नाम दिया, जिसमें वायुसेना, शाहीन और फतह मिसाइलों का उपयोग किया गया।
- भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई को "ऑपरेशन सिंदूर" नाम दिया था, जिसे 7 मई 2025 को अंजाम दिया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस – 11 मई



- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में वर्ष 1998 में किए गए सफल पोखरण-II परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है।
- पोखरण-II को "ऑपरेशन शक्ति" के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत 11 मई और 13 मई 1998 को दो चरणों में पाँच परमाणु विस्फोट किए गए थे।

- 11 मई 1998 को भारत ने तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, जिनमें एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण, एक विखंडन उपकरण और एक सब-किलोटन उपकरण शामिल था।
- भारत ने पूर्ण पोखरण-II अभियान के तहत 13 मई 1998 को दो अतिरिक्त परमाणु विखंडन परीक्षण भी किए।
- इन सफल परीक्षणों के बाद भारत परमाणु हथियार संपन्न देशों के समूह में शामिल होने वाला विश्व का छठा देश बना, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस अभियान में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भूमिका निभाई।
- जब ये परीक्षण किए गए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बाद में वर्ष 1999 में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया।
- उसी दिन भारत ने अन्य तकनीकी उपलब्धियाँ भी हासिल कीं, जिनमें बेंगलुरु में स्वदेशी हंसा-3 विमान की पहली परीक्षण उड़ान शामिल थी।
- डीआरडीओ ने 11 मई 1998 को त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भी परीक्षण किया, जिससे उसी दिन कई रक्षा तकनीकी उपलब्धियाँ दर्ज हुईं।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम “समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार” रही, जिसका उद्देश्य नैतिक और समावेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना था।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2026



- अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है।
- यह दिवस स्वास्थ्य प्रणाली, रोगी सहायता और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में नर्सों की भूमिका को रेखांकित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम “आवर नर्सेज़। आवर फ्यूचर। एम्पावर्ड नर्सेज़ सेव लाइव्स। रही।
- इस थीम की घोषणा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (आईसीएन) द्वारा की गई।
- यह थीम नर्सिंग कार्यबल में निवेश, नर्सों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें पर्याप्त संसाधन एवं स्वायत्तता प्रदान करने पर जोर देती है।

- इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज वर्ष 1965 से इस दिवस का आयोजन कर रहा है।
- वर्ष 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के सम्मान में 12 मई को आधिकारिक रूप से इस दिवस के रूप में घोषित किया गया।
- फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध के दौरान रोगी देखभाल और चिकित्सीय स्वच्छता में क्रांतिकारी सुधार किए थे।
- यह दिवस अब नर्सों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक कल्याण की रीढ़ के रूप में सम्मानित करता है।
- वर्ष 2026 का आयोजन स्वास्थ्य समानता, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, कार्यबल निवेश और मजबूत चिकित्सा प्रणालियों पर केंद्रित रहा।
- यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य संकट, दीर्घकालिक बीमारियों और आपदा प्रबंधन में नर्सों की भूमिका को भी रेखांकित करता है।
- इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नर्सिंग कार्यबल की कमी और कार्यस्थल थकान जैसी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना भी है।
- अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर आईसीएन, राष्ट्रीय नर्सिंग संघों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस 2026



- राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस 2026, 15 मई 2026 को मई के तीसरे शुक्रवार के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य विश्वभर में विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे जानवरों, पक्षियों, समुद्री प्रजातियों और पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में एंड्रेंजर्ड स्पीशीज़ कोएलिशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण और आवास सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- वर्ष 2026 की थीम “सेलीब्रेटिंग अमेरिकाज़ वाइल्डलाइफ कमबैक स्टोरीज़। चैंपियनिंग द एंड्रेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट” रही, जिसमें सफल संरक्षण प्रयासों और प्रजातियों की पुनर्बहाली को प्रमुखता दी गई।
- सरकारों, विद्यालयों, वन्यजीव संगठनों और पर्यावरण समूहों ने जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, वन्यजीव प्रश्नोत्तरी, स्वच्छता गतिविधियाँ और जैव विविधता कार्यक्रम आयोजित किए।

- संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रमुख कारणों में आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, अवैध वन्यजीव व्यापार, प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और वनों की कटाई शामिल हैं।
- भारत ने रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ और गंगा नदी डॉल्फिन जैसी प्रजातियों से जुड़े संरक्षण चुनौतियों को रेखांकित किया।

अतिरिक्त जानकारी

- भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख कानून है।
- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में और प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों के आकलन का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस है।
- विश्व वन्यजीव दिवस संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है।

सिक्किम राज्य स्थापना दिवस 2026 16 मई को मनाया गया



- सिक्किम ने 16 मई 2026 को अपना 51वाँ राज्य स्थापना दिवस मनाया, जो भारत का हिस्सा बने 51 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- सिक्किम 16 मई 1975 को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों और जनमत संग्रह के बाद आधिकारिक रूप से भारत का पूर्ण राज्य बना था।
- भारत में शामिल होने से पहले सिक्किम चोग्याल शासन के अंतर्गत नामग्याल वंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य के रूप में कार्य करता था।
- वर्ष 1970 के शुरुआती दशक में सिक्किम में लोकतांत्रिक शासन, निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी मांगें बढ़ने लगी थीं।
- वर्ष 1975 में आयोजित ऐतिहासिक जनमत संग्रह में अधिकांश लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया।
- जनमत संग्रह के बाद सिक्किम की राजशाही समाप्त कर दी गई और संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 पारित किया गया।

- भारतीय संघ में विलय के बाद सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वाँ राज्य बना।

स्थैतिक बिंदु

- सिक्किम के प्रमुख त्योहार – लोसर, सागा दावा, पांग ल्हाबसोल, दसैं और तिहार
- सिक्किम के प्रसिद्ध बौद्ध मठ – रुमटेक मठ और पेमायंग्त्से मठ
- सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य माना जाता है और यहाँ विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत कंचनजंगा स्थित है।
- वर्ष 2026 में प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं।

विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 ने मधुमक्खियों की घटती संख्या पर चिंता बढ़ाई



- विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2026 को मधुमक्खियों और परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया।
- विश्व की लगभग 90% जंगली पुष्पीय पौधियाँ और लगभग 75% खाद्य फसलें परागणकर्ताओं पर निर्भर बताई गईं।
- आवास विनाश, कीटनाशक, जलवायु परिवर्तन, रोग, प्रकाश प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक को मधुमक्खियों की घटती संख्या के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया।
- अमेरिका के वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों ने जून 2024 से मार्च 2025 के बीच 62% मधुमक्खी कॉलोनी हानि की जानकारी दी।
- मधुमक्खियों के लिए हानिकारक नियोनिकोटिनाइड कीटनाशक थायामेथोक्सम पर यूरोपीय संघ में वर्ष 2018 से प्रतिबंध जारी है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन ने परागणकर्ता-अनुकूल खेती और जैव विविधता संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया।
- ग्रीनपीस अफ्रीका ने बताया कि अफ्रीका में लगभग 40% कीट परागणकर्ता विषैले कीटनाशकों के कारण खतरे में हैं।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 22 मई को मनाया गया

- अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2026 को जैव विविधता अभिसमय के तहत मनाया गया।



- वर्ष 2026 की थीम “एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट” रखी गई।

- जैव विविधता अभिसमय पर हस्ताक्षर के लिए वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट में इसे प्रस्तुत किया गया था।
- ओडिशा के जनजातीय समुदायों को देशी बीजों, मोटे अनाजों की विविधता और जलवायु-सहिष्णु कृषि पद्धतियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से उल्लेखित किया गया।
- ओडिशा के पूर्वी घाटों में सामुदायिक बीज बैंकों ने पारंपरिक मोटे अनाज, दाल और धान की किस्मों के संरक्षण में मदद की।
- कोंध और पराजा जनजातीय महिलाओं ने बीज संरक्षण के माध्यम से फसलों की आनुवंशिक विविधता बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डाइवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना का नेतृत्व फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सामुदायिक बीज प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया गया।